www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 115 || लखनऊ
शनिवार
25 जुलाई 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदयः 05:25
सूर्यास्तः 06:59
अधिकतमः 32°00
न्यूनतमः 27°00

पेज 07

विशेष समाचार | जल संकट का असंतुलित... >>पेज 04 | कांवड़ मेले के लिए रेलवे की ... >>पेज 06 | 'सैयारा' के बाद ताबड़तोड़ ...

10 साल जेल और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, रेल नेटवर्क-रसायन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

पेपर लीक पर संशोधित बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देशभर में नीट (NEET-UG) पेपर लीक को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शनों और राजनीतिक घमासान के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को और अधिक सख्त बनाने वाले संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सरकार अगले सप्ताह मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक में पेपर लीक कराने वाले गिरोहों और इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ पहले से अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।

बिल के अनुसार, दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि कड़े कानून से परीक्षा माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया कि पेपर लीक रोकने के लिए तैयार किया गया नया संशोधन विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस कानून को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जा सके।

4,294 करोड़ के 2 बड़े फैसलों को मंजूरी

पेपर लीक पर क्या है कानून?

देश में पहले ही से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू है। सरकार नए संशोधन कर कानून को और सख्त और प्रभावशाली करने की तैयारी में है।

क्या है कानून में नियम

देश में पेपर लीक से जुड़ा जो अधिनियम लागू है, उसमें यह प्रावधान हैं।

- पेपर लीक करने परः 3 से 5 साल जेल और 10 लाख तक जुर्माना
- गिरोह शामिल होने परः 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना
- एजेंसी दोषी होने परः 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूली और अगले 4 साल परीक्षा कराने पर बैन

इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती है और समझौता नहीं हो सकता। जांच डीएसपी रैंक या उससे सीनियर अफसर करेंगे।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

सरकार ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी फैसला किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इन अदालतों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी करें और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाएं। सरकार का मानना है कि त्वरित न्याय से अपराधियों में कानून का डर बढ़ेगा और परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी। परीक्षा प्रणाली में सुधार, गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय करने तथा पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की जा रही है।

पीएम मोदी ने छात्रों को दिया भरोसा

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। करीब ढाई मिनट के इस संदेश में उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई महीनों में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वे जेल में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता थी कि छात्रों का एक साल खराब न हो, इसलिए कम समय में लगभग 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा आयोजित कराई गई और 19 जुलाई को परिणाम भी घोषित कर दिए गए।

> सरकार का कहना है कि नए संशोधन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की पेपर लीक या परीक्षा में धांधली की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

संसद से सड़क तक गरमाया मुद्दा

पेपर लीक का मामला संसद में भी लगातार गूंज रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है।

वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। नीट-यूजी पेपर लीक मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।

जांच एजेंसी अब तक विभिन्न राज्यों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और पेपर लीक से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

सरकार का कहना है कि संशोधित कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट और एजेंसियों की कार्रवाई के जरिए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

एयरफोर्स की तैनाती स्थायी हल नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को NEET परीक्षा में पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह पेपर लीक रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि सालों से अस्थायी (तदर्थ) व्यवस्थाओं के सहारे काम करने से दिक्कतें पैदा हुई हैं। अब परीक्षा की पक्की और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाई जाए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच शुक्रवार को इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें 'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) की याचिका भी शामिल है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि सरकार यह बताए कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने, राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें लागू करने और IIT मॉडल अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

पेपर लीक केस : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अफसर बर्खास्त

कानूनी और क्रिमिनल एक्शन भी होगा, एक दिन पहले शिक्षा सचिव को हटाया था

आदेश

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्रालय ने NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी सूत्रों के हवाले से यह खबर दी। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को 17 सीनियर अधिकारियों के तबादले और प्रमोशन के आदेश जारी किए थे। सबसे बड़ा फेरबदल शिक्षा मंत्रालय में हुआ था। यहां 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी नरेश पाल गंगवार को शिक्षा मंत्रालय के हायर एजुकेशन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। वे मौजूदा सचिव विनीत जोशी की जगह लेंगे।

>> (शेष पेज 06 पर)

टाइमलाइनः संसद तक कैसे पहुंचा NEET विवाद

- **3 मई**: देशभर में NEET-UG 2026 परीक्षा हुई। करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए।
- **12 मई**: पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द कर रि-एग्जाम की घोषणा की गई।
- **15 मई**: CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं।
- **16 मई**: अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया मूवमेंट शुरू किया।
- **6 जून**: कॉकरोच पार्टी ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन किया।
- **20 जून**: कॉकरोच पार्टी ने जंतर-मंतर पर दूसरा विरोध प्रदर्शन किया गया।
- **28 जून**: कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए।
- **20 जुलाई**: संसद के मानसून सत्र के पहले दिन CJP ने 'चलो संसद' मार्च निकाला। हजारों लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और टियर गैस का इस्तेमाल किया।
- **21 जुलाई**: राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया, इन्हें हिरासत में लिया गया।
- **21 जुलाई**: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने NEET, लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा उठाया, दोनों सदनों में हंगामा हुआ।
- **22 जुलाई**: विपक्ष ने संसद में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी रखा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई।
- **23 जुलाई**: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया। विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा।

दावा : वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वाने में कांग्रेस सांसद का रोल

सरकार के साथ 3 दिन चली परदे के पीछे बातचीत, प्रधान के इस्तीफे वाली मांग छोड़ी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल तुड़वाने में कांग्रेस सांसद का रोल सामने आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार और वांगचुक के बीच के गतिरोध को खत्म किया। करीब 3 दिन तक बैक-चैनल बातचीत चली। कई स्तरों पर कोशिशें की गई। इसके बाद सहमति बनाने में कामयाबी मिली। तन्खा पहले भी वांगचुक के NSA मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पैरवी कर चुके हैं। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बातचीत में लद्दाख के कुछ नेताओं ने भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अनशन तोड़ने के बाद वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।

> केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार देर रात वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया।

उनके लिए सबसे अहम बात छात्रों पर कार्रवाई रुकवानी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना जरूरी नहीं था। NEET पेपर लीक के खिलाफ वांगचुक 27 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने गुरुवार देर रात 12:30 बजे अपना अनशन खत्म कर दिया। जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इससे पहले उन्होंने मार्च 2024 में लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, पूर्ण राज्य का दर्जा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर 21 दिन की भूख हड़ताल की थी।

फास्ट न्यूज

सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता पहुंचे भीमसेना प्रमुख को रोका

गुरुग्राम। गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती सोनम वांगचुक हाल-चाल जानने पहुंचे भीमसेना प्रमुख एवं संविधान सुरक्षा पार्टी (एसए-सपी) सुप्रीमो नवाब सतपाल तंवर को अस्पताल के मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। भारी पुलिस बल द्वारा रोके जाने से नाराज तंवर ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए इसे 'खुली तानाशाही' करार दिया है।

दिल्ली पुलिस बोली- जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में 216 क्रिमिनल शामिल

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (FCR) के जरिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों की पहचान कर रही है। 216 लोग ऐसे मिले हैं जिनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है।

इनमें वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और बाकी अन्य जिलों के हैं। सूत्रों के मुताबिक, वायरल सोशल मीडिया पोस्ट, सीसीटीवी फुटेज की FCR से जांच करने पर इन क्रिमिनल्स की पहचान हुई। जंतर-मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी। कई वीडियोज ऐसे भी आए थे।

12वीं के स्टूडेंट का पोस्टर-तुम डंडे मारोगे, हम फूल देंगे

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन छात्र अपने-अपने अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से पहुंची पूजा ने अपने पोस्टर पर लिखा कि पुलिस की ड्रेस महज ड्रेस नहीं, एक वादा है। पुलिस को अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। वहीं, दिल्ली का 12वीं का स्टूडेंट ईशु एक पोस्टर लेकर पहुंचा।

धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल शिक्षा मंत्री, इस्तीफा दें : राहुल

पैलेट गन से घायल छात्र की टी-शर्ट उठाकर घाव दिखाए

प्रेस कॉन्फ्रेंस

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं।' उन्होंने छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा, 'मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया था, जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन कर रहा था।' 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च निकाला था।

>> (शेष पेज 06 पर)

प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी : आशुतोष

इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेने पर सहमति

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, 'हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।' केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, 'दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।' रैपिड एक्शन फोर्स ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान अपने जवानों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने और पैलेट गन चलाने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने एंटी रॉयट यूनिट के आईजी से कहा है कि वे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए अलग-अलग टीमों की कार्रवाई के क्रम और घटनाओं की पुष्टि करें जिनमें उन पर हमले हुए थे। CRPF अधिकारियों ने कहा कि इन घटनाओं की औपचारिक 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' अभी शुरू नहीं की गई है।

>> (शेष पेज 06 पर)

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष बोले- प्रधान के इस्तीफे से कम पर समझौता नहीं

आशुतोष ने कहा है- "इस्तीफा हो या कैबिनेट से बर्खास्तगी हो, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। सरकार ने बोला है, वह हमारी मांगें मानने तैयार है। वह प्रधान के इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखेगी। इसके बारे में हमें कल की मीटिंग में बताया जाएगा।" आशुतोष बोले- "हमें खुशी है कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा और अपनी बात प्रमुखता से रखी कि हम पर एक्शन न हो, पीड़ितों को मुआवजा मिले। उनका हंगर स्ट्राइक से जुड़ी हुई मांग थी। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है उसमें पहले दिन से हमारी मांग क्लियर है। प्रधान के इस्तीफे की मांग में कोई बदलाव नहीं हैं।"

ममता बनर्जी सोमवार को जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल होंगी

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में NEET पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। बनर्जी छात्रों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए विरोध स्थल पर जाएंगी। कोलकाता में तृणमूल की सालाना 21 जुलाई 'शहीद दिवस' रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राष्ट्रीय राजधानी में CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

सफ़ाई : कोई याचिका दाखिल ही नहीं की गई थी, पहले कहा था- वीडियो देखने का समय नहीं

सीजेपी प्रदर्शन पर याचिका ठुकराई नहीं : सीजेआई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्टों को लापरवाह और गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग बताया, जिनमें दावा किया गया था कि उन्होंने CJP के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती से जुड़े मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। CJI ने साफ किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी। सीजेआई ने यह टिप्पणी खुली अदालत में की, जब सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने एक अन्य मामले की लिस्टिंग का जिक्र किया। उन्होंने कहा- मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया कि मैंने मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- पिछले दो दिनों से पूरी तरह गलत बात कही जा रही है कि मामला दाखिल किया गया था। सुबह 10 बजे तक एक भी पन्ना दाखिल नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक प्रतिनिधित्व था, जिसे मिश्रा या किसी अन्य व्यक्ति ने भेजा था। इससे पहले बुधवार को वकील नरेंद्र मिश्रा ने दिल्ली में CJP के नेतृत्व वाले प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के आरोपों पर तत्काल सुनवाई की मांग मौखिक रूप से की थी। उस समय CJI, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने यह अनुरोध रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। बुधवार को एक वकील ने CJI की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी। CJI सूर्यकांत ने कहा था- हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। जब वकील ने छात्रों के साथ मारपीट के वीडियो देखने का दूसरी बार अनुरोध किया तो CJI ने कहा- हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए।

> "सीजेआई सूर्यकांत ने तब कहा था, कॉकरोच की तरह बहुत से युवा ऐसे हैं, जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। वे सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म बन रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो काले चोगे पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है।

सीजेआई के बयान से बनी कॉकरोच जनता पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत मई 2026 में CJI सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद हुई थी। इसे सोशल मीडिया पर बनाया गया। देखते ही देखते लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच 15 जनवरी को वकील संजय दुबे की दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता सीनियर वकील का दर्जा पाना चाहता था। जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है या न्याय व्यवस्था में भागीदारी का एक जरिया।

हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरीं, 13 की मौत

गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट

घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई। उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले के पश्चिमी भाग में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है, जिससे चंदोरी गांव में बाढ़ आ गई है। व्यापक जलभराव से घर और दुकानें जलमग्न हो गई हैं।

900 सीटों की क्षमता ■ सहारा शहर में 200 एकड़ में तैयार होगा नया परिसर

कमल जैसी बनेगी नई विधानसभा

तैयारी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ को जल्द नया विधानसभा भवन मिल सकता है। गोमती नगर के सहारा शहर में कमल की आकृति जैसा नया विधानसभा परिसर बनाने की तैयारी है। यह परिसर करीब 200 एकड़ में बनेगा। इसमें विधानसभा, विधान परिषद और संयुक्त सत्र के लिए अलग-अलग भवन होंगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगले साल निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इसे आधुनिक सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। भवन का वास्तुशिल्प कमल की आकृति जैसा होगा। यह भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश की पहचान

को दर्शाएगा। यह परियोजना केवल नया विधानसभा भवन नहीं होगी, बल्कि लखनऊ के लिए एक नया आर्किटेक्चरल लैंडमार्क भी बनेगी। आधुनिक डिजाइन, विशाल परिसर और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ यह भवन उत्तर प्रदेश की नई प्रशासनिक सोच और भविष्य की आवश्यकताओं का प्रतीक होगा। उत्तर प्रदेश के नए विधान भवन के मॉडल को ऊपर से देखने पर मुख्य विधानसभा भवन कमल की पंखुड़ियों की तरह दिखाई देगा। इस परिसर में केवल विधानसभा ही नहीं, बल्कि आधुनिक सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, विधायक हॉस्टल, और वीवीआईपी प्रशासनिक ब्लॉक भी शामिल होंगे। इस नए सदन में 700 विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के प्रतिनिधियों के लिए अलग-अलग चर्चा की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कंसलटेंट और आर्किटेक्ट के माध्यम से इसका नक्शा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा रहा है।

डिजिटल सुविधाओं से लैस होगा नया भवन

नई इमारत में 700 सदस्यों की क्षमता वाला विधानसभा सदन और 200 सदस्यों की क्षमता वाला विधान परिषद सदन बनाया जाएगा। दोनों सदनों में आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था होगी।

■ नए विधानसभा भवन का प्रस्तावित मॉडल कमल के फूल की आकृति पर आधारित है। (सांकेतिक तस्वीर)

संयुक्त सत्र के लिए 1000 सीटों का हॉल

नए विधानसभा परिसर में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र के लिए 1000 सीटों का बड़ा हॉल बनाया जाएगा। यहां बड़े सरकारी कार्यक्रम और विशेष आयोजन भी हो सकेंगे।

> प्रस्ताव के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य अगले वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। इसे उत्तर प्रदेश में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे और राजधानी लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई पहचान देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल माना जा रहा

5 हजार से ज्यादा वाहनों की पार्किंग

परिसर में 5,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके अलावा चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, प्रशासनिक कार्यालय और आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

हजरतगंज दो युवकों ने किया आत्मदाह का प्रयास

जमीन कब्जे की शिकायत पर सुनवाई न होने से थे परेशान

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के हजरतगंज में शुक्रवार को दो युवकों ने आत्मदाह की कोशिश की। दोनों डीजल से भरी बोतल लेकर पहुंचे थे और खुद पर डीजल डालने लगे। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुबग्गा निवासी चाचा-भतीजे ने आत्मदाह की कोशिश की। इनका आरोप है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कई स्तरों पर शिकायत की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसी से आहत होकर दोनों ने हजरतगंज पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और युवकों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल की जाएगी। घटना के दौरान कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से स्थिति जल्द ही सामान्य कर ली गई। लखनऊ के मलिहाबाद तहसील स्थित दुबग्गा थाना क्षेत्र के लीलाखेड़ा कटौली के रहने वाले राम गणेश और उनके भतीजे सतीश कुमार गौतम ने आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने उन्हें समय रहते बचा लिया और हजरतगंज थाने ले आए। पूछताछ पीड़ित राम गणेश ने बताया कि गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन पर उनके परिवार के ही सुनील नाम के व्यक्ति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है।

फास्ट न्यूज

इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 25 जुलाई से बदलेगा ट्रैफिक

लखनऊ । लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर लंबे समय से लगने वाली जाम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य 25 जुलाई से शुरू होगा। निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक को सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस ने अगले आदेश तक अस्थायी डायवर्जन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। जरूरत के अनुसार डायवर्जन व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

लखनऊ में 4 फर्मों और 4 कारोबारियों पर एफआईआर

लखनऊ । राजधानी लखनऊ में नकली दवाओं के कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की जांच के बाद अमीनाबाद थाने में चार फर्मों और उनके चार संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

आरोप है कि इन लोगों ने नकली और काउंटरफिट थ्रोंबोफोब ऑइंटमेंट 20gm की खरीद-बिक्री कर बाजार में बेचा और भारी मुनाफा कमाया। जांच में यह भी सामने आया कि 24 हजार ट्यूब दवा का न तो भौतिक स्टॉक मिला और न ही उसके खरीद संबंधी मूल बिल उपलब्ध कराए गए।

20 साल के युवक ने दी जान

मोहनलालगंज । लखनऊ के मोहनलालगंज में शुक्रवार सुबह एक 20 साल के युवक ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में शोक छा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान उतरगांव निवासी कमलेश लोधी (20) पुत्र स्व. नरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।

संजय कुमार पाण्डेय ग्राम्य विकास उ०प्र० को किया गया निलम्बित

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र० को, जनपद उन्नाव में उपायुक्त, (स्वतः रोजगार), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनाती की अवधि में की गयी वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथमदृष्ट्या दोषी होने व उनके द्वारा लोकपालों का कार्यकाल दिनांक 15.03.2026 को पूर्ण होने के पश्चात् उनका कार्यकाल विस्तार/नवीनीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव/पत्रा-वली प्रस्तुत नहीं करने, तथा संबंधित विशेषज्ञ के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करने, भारत सरकार के निर्देशों एवं शासनादेश का उल्लंघन करने, मनरेगा के विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर कोई उचित पर्यवेक्षण/कार्यवाही नहीं करने आदि के कारण तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है ।निलम्बन की अवधि में श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ०प्र०, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

संजय कुमार पाण्डेय के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली- 1999 के नियम -7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) ग्राम्य विकास विभाग के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

टाटा मोटर्स के जॉब फेयर में उमड़ी भीड़

लखनऊ। लखनऊ के देवा रोड स्थित टाटा मोटर्स प्लांट में शुक्रवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) के तहत जॉब फेयर आयोजित किया गया। कंपनी ने 500 अभ्यर्थियों को बुलाया था, लेकिन करीब 2,500 युवक-युवतियां पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण पहले दिन करीब 2,000 अभ्यर्थियों की ही स्क्रीनिंग हो सकी। बाकी अभ्यर्थियों को अगले दिन आने के लिए कहा गया।

जॉब फेयर में बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें पहुंचने का समय तो बताया गया था, लेकिन प्रक्रिया कितनी देर चलेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। वहीं, प्लेसमेंट सेल के अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा अभ्यर्थी आने की वजह से सभी की स्क्रीनिंग एक दिन में पूरी नहीं हो सकी। इसलिए बाकी अभ्यर्थियों को अगले दिन बुलाया गया है।

लखनऊ में युवाओं की 600मीटर लंबी कतार, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे

लिपस्टिक-नेल पॉलिश से नारे लिखे, ढपली बजाई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ में कई संगठनों के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छात्र जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध और CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) के समर्थन में जुटे हैं। इनमें AISA, SFI, NSUI और समाजवादी छात्र सभा समेत LGBTQ के लोग भी शामिल हैं।

छात्रों ने ढपली बजाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। वहीं, LGBTQ के युवक-युवतियों ने लिपस्टिक और नेल पॉलिश से पोस्टरों पर नारे लिखे। पहले सभी परिवर्तन चौक पर इकट्ठा हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए करीब 2 किमी दूर शहीद स्मारक की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भीड़ सड़क पर करीब 600

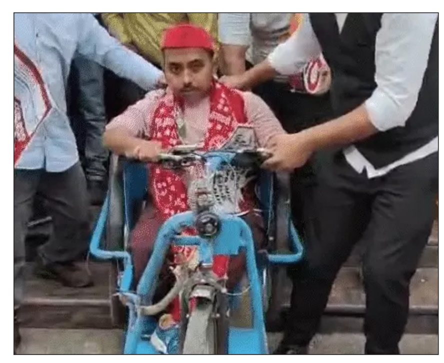

प्रदर्शन में शामिल प्रिंस प्रकाश ने कहा- यह आम छात्रों और हिंदुस्तान के युवाओं का प्रोटेस्ट है। 2027 में जनता यूपी में जवाब देगी।

मीटर लंबी कतार में है।

प्रदर्शन में शामिल हुए प्रदीप शर्मा ने कहा- देश में अब तक 158 पेपर लीक हुए हैं। NEET के पेपर लीक के सभी जिम्मेदारों को इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग छात्रों को सपोर्ट देने के लिए आज परिवर्तन स्थल से शहीद स्मारक तक मार्च निकालेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर ने कहा- यह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं, देश की शिक्षा का मसला है। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया गया है।

■ परिवर्तन चौक पर करीब 4:20 बजे युवा, महिलाओं और बुजुर्ग प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए।

धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लिखा हुआ बैनर लेकर चल रहे प्रदर्शनकारी

मार्च में सबसे आगे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो लिखा हुआ बैनर लेकर युवा चल रहे हैं। इनके पीछे जबरदस्त भीड़ है। लखनऊ के एडवा संगठन की हेड मधु गर्ग ने कहा- आज देश के हर शहर में उबाल आ गया है। यह जनता का मुद्दा है। जनता के मुद्दे पर ही राजनीति होती है।

लखनऊ और यूपी के सभी 75 जिलों में कैंडिल मार्च

नीट - लाठीचार्ज विवाद पर प्रदेशव्यापी आंदोलन

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। नीट, सीबीएसई परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तथा दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में यूपी कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी जहां आज शाम को लखनऊ में कैंडिल मार्च निकालेगी। वहीं, शनिवार को प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ कैंडिल मार्च और सत्याग्रह आयोजित करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इसे लेकर सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों को निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई बर्बरतापूर्ण था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों

पर जिस तरह बल प्रयोग किया गया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। यह आंदोलन केवल लाठीचार्ज के विरोध तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवालों को भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शनिवार को प्रदेश के सभी जनपदों में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटियों के नेतृत्व में कैंडिल मार्च निकाला जाएगा। मार्च का समापन संबंधित जिलों में महात्मा गांधी या डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर होगा, जहां सत्याग्रह भी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सी.पी. राय ने कहा कि पार्टी परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है।

> प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार आज शाम छह बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से गांधी प्रतिमा, जीपीओ तक कैंडिल मार्च निकाला जाएगा। इसमें पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और युवा बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

अजय राय बोले- छात्रों पर लाठीचार्ज अस्वीकार्य

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे पर छात्रों के साथ खड़ी है और पूरे प्रदेश में विरोध दर्ज कराएगी।

दुकानों के शटर काटकर चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया

लखनऊ। लखनऊ में बंद दुकानों को निशाना बनाकर शटर काटने वाले शातिर चोरों के गैंग का मड़ियांव पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शुक्रवार को गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 4 मोटरसाइकिलें, जनरेटर के पार्ट्स, दुकान से चोरी किया गया सामान, 44 हजार रुपए नकद, चोरी में इस्तेमाल डाला, कटर और लोहे की रॉड बरामद की है। गिरोह शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दुकानों, जनरेटर और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।

पुलिस के मुताबिक, 5 जुलाई को त्रिवेणीनगर निवासी शुभम चौरसिया की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की गई थी। इस मामले में मड़ियांव थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कोयला ढलान के पास घेराबंदी कर चार संदिग्धों को चोरी के सामान से लदे डाले के साथ पकड़ लिया।

मंत्री आवास घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों को ले गई पुलिस

युवक बेहोश, महिला के बच्चे को पुलिस ने गोद में लिया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में शुक्रवार सुबह 69 हजार शिक्षक अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सुबह करीब 11:10 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंच गए और घेराव शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर गया। जबकि अपने छोटे बच्चे के साथ पहुंची एक महिला अभ्यर्थी का बच्चा पुलिसकर्मियों ने गोद में लेकर संभाला। प्रदर्शन के दौरान करीब 60 अभ्यर्थियों ने योगी बाबा न्याय करो के नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो धक्का-मुक्की शुरू हो गई। करीब 30 मिनट तक हंगामा चला। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हाथ-पैर पकड़कर उठाया, बसों में बैठाया और हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। करीब 60 अभ्यर्थी प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लखनऊ पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ धोखा किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में 8,270 सीटों को लेकर एफिडेविट दाखिल किया है। इसमें 4,946 ऐसे अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं, जो पहले ही इस भर्ती प्रक्रिया से तीन बार बाहर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग 6,800 सीटों पर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की थी, लेकिन सरकार की नई प्रक्रिया के चलते अब केवल करीब 3,300 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति मिल पाएगी।

योजना : बुंदेलखंड के विकास को नई गति, पेयजल के साथ रोजगार और ऊर्जा क्षेत्र को भी मिलेगा नया विस्तार

बेटे-बेटियों की अच्छी शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी : ए.के. शर्मा

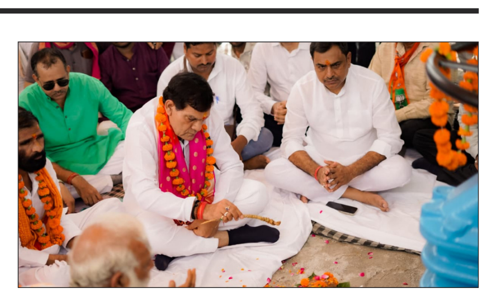

- 83.24 करोड़ की गुरसराय-गरौठा पेयजल योजना का लोकार्पण, हजारों परिवारों को मिलेगा शुद्ध पेयजल : ए.के. शर्मा
- मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड में तेजी से साकार हो रही विकास परियोजनाएं
- डिफेंस कॉरिडोर, सौर ऊर्जा और पेयजल परियोजनाएं बदलेंगी बुंदेलखंड की तस्वीर

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने झांसी जनपद में 83.24 करोड़ की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद एवं गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस परियोजना से गुरसराय और गरौठा के लगभग 7740 घरों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। अपने संबोधन में मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री

बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे

मंत्री शर्मा ने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियो-जनाओं का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इनके पूर्ण होने के बाद लोगों को बेहतर, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाएगा ।उन्होंने बुंदेलखंड में विकसित हो रहे डिफेंस कॉरिडोर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि इन परियोजनाओं का सर्वाधिक लाभ स्थानीय युवाओं को मिले। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को उनके अपने क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, जिससे पलायन रुके और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

उन्होंने कहा कि यह पेयजल परियोजना केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के स्वास्थ्य, सम्मान और बेहतर जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है।

एलआईसी बीमा सखी कार्यक्रम से आत्मनिर्भर बन रहीं ग्रामीण महिलाएँ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान

- बीमा सखियों ने छह माह में अर्जित किया रु 02 करोड़ से अधिक का सामूहिक कमीशन

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और आत्मनिर्भरता को नई गति प्रदान कर रही है। इसी दिशा में एलआईसी का बीमा सखी कार्यक्रम महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका, स्वरोजगार और वित्तीय नेतृत्व का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर बीमा सखी के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे वे अपने परिवार की

आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ-साथ ग्रामीण समाज में वित्तीय जागरूकता का भी विस्तार कर रही हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी बनाना नहीं, बल्कि उन्हें विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी और नेतृत्वकर्ता बनाना है। एलआईसी बीमा सखी कार्यक्रम इसी सोच का सशक्त उदाहरण है, जिसने हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनि-र्भरता और सम्मानजनक आजीविका के नए द्वार खोले हैं। उन्होंने कहा कि बीमा सखी कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वहीं ग्रामीण परिवारों तक बीमा सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी प्रभावी ढंग से पहुँच रहा है। आज बीमा सखियाँ अपने कार्य से न केवल परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन रही हैं, बल्कि अपने गाँवों में वित्तीय जागरूकता, महिला सशक्ति-करण और सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक के रूप में भी नई पहचान स्थापित कर रही हैं। मौर्य ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं तथा स्वयं सहायता समूहों की सशक्त भागीदारी से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक गति पकड़ेगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर दिए निर्देश, 6 हजार से अधिक सीसीटीवी से निगरानी होगी

डीएम ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की

तैयारियां

तमसा संकते, एजेंसी

उन्नाव। आगामी कांवड़ यात्रा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा मार्गों की सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधाओं और श्रद्धालुओं की अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम ने जलाभिषेक

वाले प्रमुख मंदिरों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की जाए तथा प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग बनाए जाएं। मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने नगर निकायों को यात्रा मार्गों की नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण, मोबाइल शौचालय और चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त एंबुलेंस, मेडिकल टीम और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने को कहा गया। वहीं विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा ढीले और जर्जर बिजली तारों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर विश्राम स्थलों की पहचान करने, कंट्रोल रूम स्थापित करने और प्रमुख स्थानों पर फायर ब्रिगेड की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सड़क किनारे उगी घास की कटाई और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने को कहा गया।

यात्रा मार्गों का संयुक्त निरीक्षण कर दूर होंगी कमियां

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों से कांवड़ यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से यात्रा मार्गों का निरीक्षण करें और जहां भी कोई कमी मिले, उसे तत्काल दूर कराया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गंगा घाटों पर नाविक और गोताखोर रहेंगे तैनात

गंगाजल लेने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने सभी प्रमुख घाटों पर नाविकों और प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती के निर्देश दिए। गहरे पानी वाले स्थानों पर बल्लियां लगाकर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। घाटों और मंदिरों पर रात के समय भी पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।

6 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यात्रा मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा पूरे कांवड़ मार्ग पर 6 हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने जलाभिषेक के प्रमुख दिनों में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग करने का भी फैसला लिया है।

"बैठक के अंत में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करने, व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करने और किसी भी शिकायत या समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डिप्टी डायरेक्टर को 10 हजार की घूस लेते पकड़ा

विजिलेंस टीम मुरादाबाद से पकड़कर बरेली ले गई

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद में बरेली विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के डिप्टी डारेक्टर को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बीज सत्यापन और टैग जारी करने के नाम पर किसान से 70 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

बरेली उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान एसपी ने बताया-उपनिदेशक रूप सिंह ने बीज सत्यापन और टैग जारी करने के एवज में एक किसान से 70 हजार रुपए की मांग की थी। किसान ने इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थता जताई तो आरोपी ने 10 हजार रुपए तत्काल और बाकी राशि अगस्त के दूसरे सप्ताह में देने की बात तय कर ली। इसके

बाद किसान ने पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान बरेली सेक्टर से मामले की लिखित शिकायत की। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर विजिलेंस टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। शुक्रवार को विजिलेंस टीम ने मुरादाबाद में शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की नकद रिश्वत लेते समय उपनिदेशक रूप सिंह को रंगे हाथ पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

फास्ट न्यूज

घर में घुसकर पति-पत्नी को पीटा

हरदोई। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में खेत में जानवर ले जाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने एक दंपति को घर में घुसकर लाठी-डंडों से पीटा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब पीड़ित महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष उसे और उसके पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहा है। महिला ने शुक्रवार की सुबह करीब 11:45 बजे प्रार्थना पत्र दिया।

गंगा का जलस्तर 24-घण्टे में 5 सेमी बढ़ा

उन्नाव। उन्नाव के शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर शुक्रवार को एक बार फिर बढ़ गया। हालांकि यह अभी खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन नवीन गंगा पुल से रेलवे पुल के बीच तेज कटान ने तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही हैं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर 109 .750 मीटर दर्ज किया गया था। शुक्रवार सुबह 8 बजे भी जलस्तर 109 .750 मीटर रहा, लेकिन दोपहर 12 बजे तक इसमें 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

गोली लगने से घायल युवक की केजीएमयू में मौत

हरदोई। हरदोई के संडीला कस्बे में पुराने रुपये के लेनदेन के विवाद में गोली लगने से घायल शिवम जायसवाल की लखनऊ के KGMU ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि अब मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। सभी नामजद आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। घटना 21 जुलाई की रात संडीला कस्बे के बांगरमऊ बस अड्डे के पास हुई थी।

युवक का शव फंदे से लटका मिला

पत्नी की साड़ी से लगाई फांसी, 15 जुलाई को जालंधर से लौटा था घर

तमसा संकते, एजेंसी

हरदोई। जिले के पिहानी कोतवाली क्षेत्र के शेखवापुर कल्याणी गांव में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय बसंत कुमार पुत्र निर्मल कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बसंत कुमार अपनी पत्नी सुनीता और तीन बेटों के साथ पंजाब के जालंधर में रहकर मजदूरी करते थे। परिवार का गुजर-बसर वहीं से होता था। करीब 10 दिन पहले, 15 जुलाई को वह अपने परिवार को जालंधर में छोड़कर अकेले अपने

पैतृक गांव शेखवापुर कल्याणी लौट आए थे। गांव लौटने के बाद वह अपने घर पर अकेले रह रहे थे। परिजनों ने बताया कि बसंत कुमार तीन भाइयों में इकलौते जीवित सदस्य थे। उनके दोनों भाइयों का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में उनकी दो विवाहित बहनें भी हैं। इस घटना के बाद पूरे परिवार में शोक का माहौल है। मृतक के रिश्ते के भाई पप्पू ने बताया कि गुरुवार को उनकी बसंत कुमार से मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच खेत में यूकेलिप्टिस के पौधे लगाने को लेकर बातचीत हुई थी। उस दौरान बसंत सामान्य व्यवहार कर रहे थे और किसी प्रकार की परेशानी या तनाव के संकेत नहीं मिले थे। शुक्रवार सुबह जब काफी देर तक बसंत कुमार घर से बाहर नहीं निकले तो रिश्ते के भाई पप्पू उन्हें बुलाने पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था।

सुबह बुलाने पहुंचे रिश्तेदार ने देखा शव

रिश्ते के भाई पप्पू ने बताया कि गुरुवार को बसंत कुमार से खेत में यूकेलिप्टिस के पौधे लगाने को लेकर बातचीत हुई थी और उस समय वह सामान्य दिखाई दे रहे थे। शुक्रवार सुबह काफी देर तक बाहर नहीं आने पर वह उन्हें बुलाने घर पहुंचे। मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद छत के रास्ते ऊपर पहुंचे तो बसंत कुमार का शव फंदे से लटका मिला।

पत्नी की साड़ी से बनाया था फंदा

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, बसंत कुमार का शव उनकी पत्नी की साड़ी के पल्लू से बने फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने आसपास के लोगों और परिजनों से पूछताछ की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मृत्यु के कारण स्पष्ट नहीं हैं और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

स्कूल पर टीसी के लिए 2 हजार मांगने का आरोप

उन्नाव में छात्रा की मां ने एसडीएम से की शिकायत, दो दिन बाद भी कार्रवाई नहीं

तमसा संकते, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र में एक निजी विद्यालय पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने के नाम पर 2 हजार रुपये की अतिरिक्त रकम मांगने का आरोप लगा है। छात्रा की मां ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को शिकायत देकर मामले की जांच कराने और बिना अतिरिक्त शुल्क के तत्काल टीसी जारी कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि शिकायत दिए दो दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिकायतकर्ता अंजली सिंह, ग्राम धीरखेड़ा मजरा संदाना, विकासखंड हसनगंज की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी आकृति सिंह ने राजदेवी शिवशंकर सिंह ग्लोबल कॉलेज,

मौलाबाकीपुर में कक्षा 10 तक पढ़ाई की है। पारिवारिक कारणों से अब वह बेटी का दाखिला दूसरे विद्यालय में कराना चाहती हैं, जिसके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अंजली सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने विद्यालय प्रशासन से टीसी जारी करने का अनुरोध किया तो उनसे नियमों के विपरीत 2 हजार रुपये अतिरिक्त देने की मांग की गई। उनका कहना है कि वह पहले ही विद्यालय की एक वर्ष की निर्धारित 18,500 रुपये की पूरी फीस जमा कर चुकी हैं और किसी प्रकार का कोई शुल्क बकाया नहीं है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि सभी देय शुल्क जमा होने के बावजूद टीसी के नाम पर अतिरिक्त धनराशि मांगना अवैध और नियमों के विरुद्ध है। शिकायतकर्ता ने एसडीएम शालिनी तोमर से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर, आरोप सही पाए जाने पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तत्काल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। एसडीएम शालिनी तोमर ने शिकायत मिलने के बाद जांच के आदेश दिए हैं।

अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम को कोर्ट का नोटिस

शैक्षिक योग्यता छिपाने के आरोप में 27 जुलाई तक मांगा जवाब

तमसा संकेत, एजेंसी

अलीगढ़। अलीगढ़ में भाजपा सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज न करने के आरोपों को लेकर एमपी-एमएलए मामलों की विशेष अदालत (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय) ने गुरुवार शाम करीब 6 बजे उन्हें नोटिस जारी किया है। अदालत ने सांसद को 27 जुलाई से पहले अपना पक्ष और आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला देहलीगेट क्षेत्र स्थित केवल विहार कॉलोनी निवासी और भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम द्वारा दायर परिवाद से जुड़ा है। परिवाद में

आरोप लगाया गया है कि सांसद सतीश गौतम ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय अपनी शैक्षिक योग्यता का पूरा और स्पष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि उनके शपथपत्र में वर्ष 2023 में स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय से स्नातक और वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होने का उल्लेख है, लेकिन संबंधित शैक्षिक दस्तावेजों और विवरणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया गया और तथ्यों को छिपाकर चुनाव लड़ा गया। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह जनप्रतिनिधित्व से जुड़े नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही नामांकन पत्र की जांच कराने और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए पहले ही परिवाद दर्ज कर लिया था। अब न्यायालय ने सांसद को अंतिम अवसर देते हुए नोटिस जारी किया है।

सपा का पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन

प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल ने संगठन मजबूत करने और लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र स्थित एक लॉन में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) का पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग तीन घंटे तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सम्मेलन में नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने संबोधन में श्यामलाल पाल ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सफलता की कुंजी बूथ स्तर की मजबूती है।

उन्होंने प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष से अपने-अपने क्षेत्र में संगठन को सशक्त बनाने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि बूथ मजबूत होगा तो विधानसभा और प्रदेश में जीत का मार्ग भी आसान होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह सम्मेलन विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है तथा आम जनता, युवाओं और बेरोजगारों की आवाज उठाना पार्टी की प्राथमिकता है। श्यामलाल पाल ने हाल के छात्र आंदोलनों और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित किया है और केवल अधिकारियों को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही, छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले छात्रों पर बल प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं का समाधान करने और प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और विचारधारा को पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन के दौरान संगठन विस्तार, बूथ प्रबंधन और आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अभियान : गांधी चौराहे से नगर पालिका तक हटाया अतिक्रमण, दुकानदारों को चेतावनी

कांवड़ यात्रा से पहले उन्नाव में चला बुलडोजर

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा-2026 को देखते हुए उन्नाव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे गांधी नगर तिराहा से शुरू हुए अभियान में नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क, फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान जेसीबी से अस्थायी ढांचे हटाए गए और दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे बने अस्थायी ढांचे, टीन शेड, फुटपाथ पर रखा सामान और नालियों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। कई

दुकानदारों ने कार्रवाई से पहले ही अपना सामान स्वयं हटा लिया, जबकि शेष स्थानों पर नगर पालिका की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। शुक्रवार को गांधी चौराहे से बड़ा चौराहा होते हुए नगर पालिका कार्यालय तक कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की सभी प्रमुख सड़कों पर चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। अगले चरण की रूपरेखा समीक्षा के बाद तय की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, अभियान शुरू करने से पहले संबंधित क्षेत्रों में मुनादी कराकर लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूरे अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कहीं भी कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित नहीं हुई। प्रशासन ने व्यापारियों और आम नागरिकों से सड़क, फुटपाथ और नालियों पर अतिक्रमण न करने तथा शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग की अपील की

कांवड़ियों के निर्बाध आवागमन के लिए कार्रवाई

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) रामाश्रय ने बताया कि अभियान शासन और जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के निर्बाध आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करना और शहर की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि नाली से नाली तक किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। फुटपाथ पर रखा सामान भी हटवाया जा रहा है, ताकि पैदल यात्रियों और वाहनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

"प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अभियान जारी रहेगा।

26वीं जगन्नाथ रथ यात्रा का सफल आयोजन

उन्नाव में नगरवासियों ने जताया आभार, अधिकारी और स्वयंसेवक भी सम्मानित

तमसा संकेत, एजेंसी

उन्नाव। उन्नाव के शुक्लागंज में 26वीं श्रीमद् भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के सफल, सुरक्षित और शांतिपूर्ण आयोजन के बाद शुक्रवार को सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजधानी मार्ग स्थित सब्जी मंडी परिसर में हुए इस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों, श्रद्धालुओं और रथ यात्रा समिति के पदाधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला का सम्मान किया। उन्हें पुष्पमालाएं पहनाई गईं और स्मृति चिह्न भेंट किए गए। श्रीमद् भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पिछले 26 सालों से शुक्लागंज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। इस साल भी हजारों श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में भाग लिया।

भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के सफल आयोजन के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

आयोजन के दौरान सुरक्षा, यातायात, साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीरेंद्र शुक्ला के नेतृत्व, दूरदर्शिता और प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय की सराहना की। उनके प्रयासों के कारण ही यात्रा का संचालन सफलतापूर्वक हो सका। समिति के पदाधिकारियों, स्वयंसेवकों, पुलिस प्रशासन और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से यात्रा के प्रत्येक चरण पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वीरेंद्र शुक्ला ने सभी नगरवासियों, समिति के सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का सम्मान है।

सम्पादकीय

गतिरोध की राजनीति

प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के आरोपितों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की जो घोषणा की, वह उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा होता कि इस विषय पर वे समय रहते देश को सीधे तौर पर संबोधित करते। इससे लोगों और खासकर छात्रों के इस भरोसे को बल मिलता कि सरकार इस मामले के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के प्रति सचमुच प्रतिबद्ध है।

जैसे नीट मामले में प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर वक्तव्य आने में देरी हुई, वैसे ही इस प्रकरण को लेकर धरने पर बैठे समूह काकरोच जनता पार्टी से संपर्क-संवाद करने में भी। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल सीजेपी के संसद मार्च में हिंसा हुई, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों को भी मौका मिल गया। इसके पहले मौका उन्हें भी मिला, जो सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होकर अराजकता फैलाने का इरादा रखते थे। वे अपने इरादे में इसलिए सफल रहे, क्योंकि पुलिस न तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और न ही उसकी उग्रता का। पुलिस के पास शायद अचानक उमड़ी और संसद भवन जाने को उतावली भीड़ से निपटने की कोई ठोस रणनीति या तैयारी नहीं थी। इसके अभाव में ही उसे सख्ती का सहारा लेना पड़ा, जो स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा बन गई है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उसने यह मांग रख दी है कि संसद तब चलेगी, जब पुलिस की सख्ती पर प्रधानमंत्री माफी मांगने के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र लेंगे।

विपक्षी दलों जैसा रवैया सीजेपी ने भी अपना लिया है। वह अपनी शर्तों के साथ-साथ अपने बताए ठिकाने पर सरकार से बात करने पर अड़ गई है। अब उसके लोग किसी मंत्री के घर या दफ्तर बात करने के लिए तैयार नहीं। यह हठधर्मिता है। इससे विचित्र और कुछ नहीं हो सकता कि गतिरोध इस पर कायम हो जाए कि बात कहां होनी चाहिए? कहना कठिन है कि उसके और सरकार के बीच का गतिरोध कैसे टूटेगा?

लगता है जैसे विपक्ष की दिलचस्पी संसद चलने देने में नहीं, वैसे ही सीजेपी की भी पहली प्राथमिकता परीक्षा व्यवस्था में सुधार की नहीं दिखती। उसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र दिखता है। इस हिसाब से तो उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के त्यागपत्र मांगे जाने चाहिए, जहां पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक हुए हैं।

छात्र हित के नाम पर की जा रही इस राजनीति के बीच सरकार को यह सचमुच सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक के दोषियों को सच में समय पर कठोर दंड मिले। इसके लिए सीबीआई को भी तत्परता दिखानी होगी। यह शुभ संकेत नहीं कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित के खिलाफ सीबीआई को कोई प्रमाण नहीं मिले।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन अस्तित्व पर मंडराता खतरा

> भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं।

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है। इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया। जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके।

भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि 'जल बचाना ही भविष्य बचाना है।' हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है।

ललित गर्ग

पिछले एक दशक ...

कुमार कृष्णन

जब युवा सवाल बन जाते हैं

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं होती कि सत्ता बहुत शक्तिशाली हो जाती है; वह तब पैदा होती है, जब समाज प्रश्न पूछना छोड़ देता है। नागरिकों की चुप्पी, विश्वविद्यालयों का मौन और युवाओं का केवल निजी सफलता तक सीमित हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता। इसके विपरीत, जब युवा व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, तब वह केवल विरोध नहीं होता; वह लोकतंत्र की आत्मा के भीतर उठती नई हलचल का संकेत होता है।

देश में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार के प्रश्नों को लेकर उभरे छात्र-युवा आंदोलन को इसी व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। इसे केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित कर देना उसकी प्रकृति को छोटा कर देना होगा। यह उस पीढ़ी की बेचैनी है जिसने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, रोजगार की अनिश्चितता झेली और अब अपनी मेहनत से अधिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए विवश हो रही है।

दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन कुछ ही दिनों में अनेक राज्यों तक फैल गया। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई ने इस बहस को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया।

लाठीचार्ज, आँसू गैस, घायल छात्र और तनावपूर्ण हालात ने एक मूलभूत प्रश्न सामने रखा—क्या लोकतंत्र में असहमति का पहला उत्तर पुलिस बल होना चाहिए, या संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए?

निस्संदेह, कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार का दायित्व है। यदि हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन हस्तक्षेप करेगा ही। लेकिन लोकतंत्र की परिपक्वता का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि उसने कानून कैसे लागू किया; उससे भी अधिक इस बात से होता है कि उसने असंतोष को समय रहते सुना या नहीं। संवाद की विफलता अक्सर टकराव का पहला कारण बनती है।

इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसने नई पीढ़ी को लेकर बनी कई रूढ़ धारणाओं को तोड़ दिया है। लंबे समय से कहा जाता रहा कि आज का युवा केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निजी करियर तक सीमित है। लेकिन जंतर-मंतर, पटना और देश के अनेक शहरों में दिखाई देने वाली भीड़ ने इस धारणा को चुनौती दी। हजारों छात्र-छात्राएँ अपनी पढ़ाई, नौकरी और निजी सुविधाएँ छोड़कर सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में युवतियों की सक्रिय भागीदारी ने इस आंदोलन को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। अनेक युवतियों ने कहा कि आंदोलन के बीच उन्हें बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हुआ। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की नैतिक शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण शायद ही हो। यह मान लेना भी भूल होगी कि यह असंतोष अचानक पैदा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार हो रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल, भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार विलंब, बेरोज़गारी का दबाव, शिक्षा की बढ़ती लागत और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना—इन सबने मिलकर युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब किसी समाज का परिश्रमी युवा अपनी प्रतिभा से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, तब यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रहती; यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसे का संकट बन जाती है।

पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा धार्मिक, सांस्कृतिक और पहचान आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। इन विषयों का अपना महत्व है, लेकिन इसी दौरान शिक्षा, विश्वविद्यालयों, शोध, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे प्रश्न धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस के हाशिए पर चले गए। वर्तमान छात्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शायद यही है कि उसने राष्ट्रीय विमर्श को फिर उन प्रश्नों की ओर मोड़ दिया है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों युवाओं के भविष्य से है।

इतिहास बताता है कि जब भी युवाओं ने अपने समय के बुनियादी प्रश्नों को लेकर आवाज़ उठाई है, तब राजनीति को अपनी भाषा बदलनी पड़ी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक गति दी। 1974 के छात्र आंदोलन ने लोकतंत्र और जवाबदेही की बहस को नई दिशा दी। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रीय प्रश्न बनाया।

योजना के...

बी0एल0यादव

मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र बेघरों को मिल रहा है आवास

समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब विकास की धारा उन लोगों तक भी पहुंचे जो लंबे समय तक मुख्यधारा से दूर रहे हैं। जिन परिवारों के पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं होता, उनके सामने केवल आवास का संकट नहीं होता, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सम्मान जैसी अनेक चुनौतियां भी खड़ी होती हैं। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उन वर्गों को प्राथमिकता दी है, जो वर्षों से आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आज प्रदेश के लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संचालित यह योजना उन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करा रही है जो प्राकृतिक आपदाओं, गंभीर बीमारियों, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण सुरक्षित आवास से वंचित थे। इस योजना के अंतर्गत वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया/गढ़इया लोहार, बैगा, चेरो, नट, बोक्सा, बंजारा, बांसफोर, बसोड़, धरकार, सपेरा, जोगी जैसे वंचित समुदायों के साथ-साथ दिव्यांगजन, कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवार, कालाजार एवं जेई/एईएस से प्रभावित परिवार, प्राकृतिक आपदा पीड़ित तथा पति के मृत्योपरांत निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के शुभारंभ से लेकर वर्ष 2025-26 तक कुल 4.72 लाख आवासों का आवंटन किया जा चुका है, जिनमें से 4.55 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। लगभग 93.36 प्रतिशत आवास पूर्णता यह दर्शाती है कि योजना केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारी जा रही है। योजना के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब तक 1.35 लाख से अधिक दिव्यांगजन, 1.07 लाख से अधिक प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार, 74 हजार से अधिक निराश्रित विधवा महिलाएं, 50 हजार से अधिक मुसहर परिवार, 33 हजार से अधिक कोल समुदाय, करीब 10 हजार थारू परिवार सहित अनेक विशेष वर्गों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। यह आंकड़े सामाजिक न्याय के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 1.16 लाख नए आवासों का बजटीय प्रावधान किया है। इनमें से 52 हजार आवासों का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है तथा शेष प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही हाल ही में जारी शासनादेश के माध्यम से प्रदेश में निवासरत सभी जनजातियों को भी योजना की प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है, जिससे अधिक से अधिक पात्र परिवार लाभान्वित हो सकें।

योजना के अंतर्गत कई जनपदों में क्लस्टर आधारित आवास निर्माण किया जा रहा है। खीरी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर तथा सोनभद्र जैसे जनपदों में विकसित हो रहे आवासीय क्लस्टर ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं।

शब्द

हमारे द्वारा अभिव्यक्ति का साधन भाषा है और शब्दों का चयन भाषा को सुसंस्कारित बनाती है। हमारे जीवन में शब्द की एक सही चोट, जीवन की दिशा-दशा को बदल सकती है। सूरज की एक किरण, तिमिर के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकती है। महत्व क्षमता और शक्ति का है, केवल फैलाव या विस्तार का नहीं हैं । जहर की एक बूंद हजारों प्राणों का, क्षण मे हरण कर सकती है। शब्द और अर्थ का आपसी सम्बन्ध अत्यंत गहन हैं । शब्द केवल ध्वनि या अक्षरों का समूह नहीं हैं , बल्कि वह अर्थ की वह वेदिका हैं, जिसमें ज्ञान और अनुभति संचित होती हैं । शब्द एक प्रकार का शरीर हैं और अर्थ उसकी आत्मा होता हैं । कभी शब्द कटोरे के समान होता हैं, जिसमें अर्थ का दूध संचित रहता हैं , कभी म्यान की तरह , जिसमें तलवार रूपी अर्थ सुरक्षित रहता हैं। इसी प्रकार शब्द एक पेटी, मंजूषा या तिजोरी का रूप भी धारण करता हैं , जिसमें अर्थ का समान या आभूषण सुरक्षित रहता हैं । ज्ञान की प्राप्ति में शब्द का महत्व अत्यंत हैं । संसार के महान प्रवचनकार अपने शब्दों के माध्यम से दूसरों को प्रबद्ध करते हैं । शब्द की उपेक्षा करके ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करना अक्सर निरर्थक साबित हो सकता हैं । शब्द में भी सहलाने की या दर्द देने की , मलहम की और कुरेदने की , निर्माण की और बर्बादी की , सुलझाने की और उलझाने की , शांति की और फ़साद की आदि - आदि ताक़त होती हैं । ये सारा विवेक , समय ,क्षेत्र भाव और सीमा पर निर्भर है । बहुत पुरानी बात याद आती है कि works Hard , He works hardly. वे जबरदस्त नेता है , वे जबरदस्ती के नेता है। खाइये खाइये शर्माए नहीं , खाइये खाइये शर्म तो है नहीं। हमारे जीवन में भाषा विवेक पर बहुत ही महत्वपूर्ण परामर्श हैं । वह शब्दो के हेरफेर से केसर भी कैंसर बन जाता है और क्षीरसागर खारा सागर बन जाता हैं । इंसान विचारों को वश में रख शब्द बनाता हैं और शब्दों को वश में रख वो भाव प्रकट करता हैं । और शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से समझ आता है अन्यथा स्वागत तो पायदान पर भी लिखा होता है । इसलिए मन की पवित्रता पर मनुष्य का व्यक्तित्व निर्भर है।

> प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

सोनभद्र में बेटियों के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला बनी 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'

उत्तर प्रदेश को महिला सशक्तिकरण, समानता और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' जनपद सोनभद्र में बालिकाओं के स्वर्णिम भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला साबित हो रही है। यह महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शी योजना जिले के शहरी क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण और वनांचल इलाकों तक बेटियों के जन्म से लेकर उनकी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक निरंतर आर्थिक संबल प्रदान कर समाज में एक नई चेतना का संचार कर रही है। राज्य सरकार की इस युगांतकारी पहल का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या जैसी अमानवीय कुरीतियों को समूल नष्ट करना, बाल विवाह की कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा के स्तर में ऐतिहासिक सुधार के साथ समान सामाजिक स्तर पर लाकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है। जनपद सोनभद्र में इस कल्याणकारी नीति ने बेटियों के प्रति समाज के पारंपरिक और संकीर्ण दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे अब बेटियों का जन्म किसी परिवार पर आर्थिक भार नहीं, बल्कि गौरव और सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा है। जनपद सोनभद्र में जिला प्रशासन के संवेदनशील प्रयासों और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के फलस्वरूप इस योजना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले लिया बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुल 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता को छह सुव्यवस्थित चरणों में विभाजित किया गया है।

योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद में बालिका के जन्म होने पर (एक वर्ष के भीतर आवेदन करने की स्थिति में) 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे नवजात बेटी के शुरुआती लालन-पालन, पोषण और देखभाल में परिवारों को अत्यंत महत्वपूर्ण संबल मिल रहा है। इसके पश्चात द्वितीय चरण में बालिका के एक वर्ष की आयु तक के सभी अनिवार्य एवं जानलेवा बीमारियों से बचाव वाले टीकों के पूर्ण होने पर 2,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। जनपद सोनभद्र में इस चरण की सफलता से जहां एक ओर समयबद्ध संपूर्ण टीकाकरण को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है, वहीं दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक कमी दर्ज की गई है, जो प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी दूरदर्शी सोच का जीवंत प्रमाण है। शिक्षा को बालिका सशक्तिकरण का सबसे सशक्त और स्थायी माध्यम मानते हुए प्रदेश सरकार ने इस योजना को विद्यालयी शिक्षा के हर स्तर से अत्यंत प्रभावी ढंग से जोड़ा है। जनपद सोनभद्र में बेटियों के प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में नामांकन को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा ड्रॉप-आउट दर को शून्य पर लाने के लिए तृतीय और चतुर्थ चरण के तहत महत्वपूर्ण आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तृतीय चरण में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये तथा चतुर्थ चरण के तहत छठी कक्षा में दाखिला लेने पर पुनः 3,000 रुपये की सहायता राशि अभिभावकों के खातों में भेजी जा रही है। इस वित्तीय व्यवस्था ने जिले के गरीब और सीमित संसाधनों वाले परिवारों को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया है, जिससे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं की भागीदारी में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। इसके आगे, किशोरावस्था में बेटियों की शिक्षा बाधित न हो और वे उच्च कक्षाओं की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा सकें, इसके लिए पंचम श्रेणी के अंतर्गत कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर बालिका को 5,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में यह आर्थिक संबल माध्यमिक स्तर पर बेटियों के पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने और उन्हें अपनी शैक्षणिक यात्रा जारी रखने में एक रक्षा कवच का कार्य कर रहा है। योजना के छठे एवं अंतिम चरण के तहत बालिका द्वारा 10वीं या 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक अथवा न्यूनतम दो वर्ष की अवधि वाले व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये की एकमुश्त महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। जनपद सोनभद्र में इस प्रावधान ने उन मेधावी एवं महत्वाकांक्षी बेटियों के सपनों को नए पंख दिए हैं, जो पहले उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों की फीस और अन्य खर्चों के डर से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को विवश हो जाती थीं। आज प्रदेश सरकार के इस संबल से जिले की बेटियां इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण कर रही हैं। आंकड़ों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जनपद सोनभद्र में जन्म और टीकाकरण से लेकर उच्च स्तर की शिक्षा तक, हर पड़ाव पर हजारों बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित होकर अपने सपनों को साकार कर रही हैं। प्रदेश सरकार सुशासन, पूर्ण पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को निभाते हुए योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के मध्यस्थ या बिचौलिए की भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर चुकी है। जनपद सोनभद्र के समस्त पात्र लाभार्थियों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायताओं का भुगतान सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से उनके या उनके अभिभावकों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

सिर से सटाकर फायर किया, आधा चेहरा उड़ा, रात में पिता राइफल घर लाए थे

12वीं के छात्र ने राइफल से खुद को गोली मारकर दी जान

आत्महत्या

- गोली लगने से छात्र का चेहरा बिगड़ गया था। आसपास खून बिखरा था।
- पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। आगरा में 18 साल के एक लड़के ने शुक्रवार सुबह खुद को गोली मारकर जान दे दी। वह इंटर मीडिएट का छात्र और

आदित्य शर्मा, मृतक

अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था।

पिता गुरुवार रात ही लाइसेंसी राइफल घर लेकर आए थे। सुबह करीब 10 बजे छात्र ने

◆ **पिता सुदीप ने बताया, आदित्य दो-तीन साल पहले डिप्रेशन में रहता था। बात-बात पर गुस्सा हो जाता था। उसका इलाज कराया था। तब वह ठीक हो गया था। हाल के दिनों में वह सामान्य व्यवहार कर रहा था। कोई भी परेशानी नहीं थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया।**

खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अपने सिर से सटाकर गोली मार ली।

जिससे उसका आधा चेहरा उड़ गया है। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

बच्चे की इस आत्मघाती कदम से परिवार गहरे सदमे में है। उसने ऐसा क्यों किया, वजह सामने नहीं आई है।

पुलिस ने लोगों से पूछताछ की है।

सुबह स्कूल नहीं गया, कमरे में खुद को कर लिया बंद

शुक्रवार सुबह आदित्य स्कूल नहीं गया। वह छत पर बने कमरे में सो रहा था। परिवार के लोगों को लगा कि देर रात तक जागने के कारण वह आराम कर रहा होगा। कुछ देर बाद मां आदित्य को उठाने के लिए पहुंची तो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मां छत से नीचे आ गई और अपने काम में बिजी हो गईं।

सुबह करीब 10 बजे आदित्य ने राइफल से खुद को गोली मार ली। फायरिंग से घर में अफरा-तफरी मच गई। मां-बाप और पड़ोसी छत की ओर दौड़े। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दरवाजा तोड़ अंदर दाखिल हुई तो आदित्य खून से लथपथ मिला। उसका आधा चेहरा गायब था।

रात ढाई बजे घर पहुंचे थे पिता, बेटे ने ही खोला था दरवाजा

घटना बाह थाना क्षेत्र की टीचर्स कॉलोनी की है। यहां रहने वाला आदित्य शर्मा (18 साल) 12वीं का छात्र था। उसकी मां डोली गृहिणी हैं। पिता सुदीप शर्मा राजस्थान की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हैं। काम के सिलसिले में वह अक्सर बाहर रहते हैं। परिजनों के अनुसार, गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे सुदीप शर्मा घर पहुंचे थे। उस समय आदित्य जाग रहा था। पिता जब आए, तो उसने ही घर का दरवाजा खोला था। सुदीप ने राइफल कमरे में संदूक के ऊपर रख दी थी, फिर सोने चले गए। उन्हें उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इतना बड़ा हादसा हो जाएगा।

सिपाही ने नाबालिग से रेप कर धर्मांतरण कराया

बाराबंकी में दो बार अबॉर्शन, चलती कार में दोस्त से जबरन शादी कराई

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। बारांबकी में एक सिपाही ने 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया। लड़की गर्भवती हो गई तो दवा खिलाकर उसका अबॉर्शन करा दिया। मामला बढ़ा तो मौलाना की मदद से चलती कार में दोस्त के साथ उसका निकाह करवा दिया। नाबालिग की मां ने गुरुवार रात एसपी विजय वर्गीय से मुलाकात करके मामले की शिकायत की। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से सिपाही और उसके साथी मां-बेटी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसपी के निर्देश पर फतेहपुर कोतवाली में सिपाही, मौलाना समेत 4 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। नाबालिग की मां ने पुलिस को बताया- मेरे पति की कई साल पहले

■ तस्वीर आरोपी सिपाही आसिफ की है। उसी ने लड़की का नंबर सऊदी में रहने वाले दोस्त को दिया था।

बीमारी से मौत हो चुकी है। मैं अपनी 16 साल की बेटी के साथ किराए के मकान में रहती हूं। बेटी ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई है। मेरी बेटी का साल 2024 फतेहपुर कोतवाली में तैनात सिपाही आसिफ से संपर्क हुआ।

फास्ट न्यूज

बंधक जमीन फर्जी दस्तावेजों से बेचने का आरोप

सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में फाइनेंस कंपनी से लिए गए 2 लाख रुपये के व्यापारिक ऋण की अदायगी न करने और बंधक रखी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने के आरोप में एक महिला के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लंभुआ क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने 30 जनवरी 2020 को कंपनी से 2 लाख रुपये का व्यापारिक ऋण लिया था।

इटावा-बरेली नेशनल हाईवे पर 3 किमी लंबा जाम

फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद शहर में इटावा-बरेली नेशनल हाईवे पर स्थित पांचाल घाट पुल पर एक ज्वाइंट खुल जाने के कारण शुक्रवार को वन-वे व्यवस्था लागू करनी पड़ी। मरम्मत कार्य के चलते पुल पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई, जिससे दोनों तरफ 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शाम 5 बजे तक यही स्थिति बनी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह घटना करीब एक सप्ताह पहले हुए मरम्मत कार्य के बावजूद हुई है। इटावा-बरेली नेशनल हाईवे पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है।

शादी का झांसा देकर युवकी से रेप

कानपुर। कानपुर में शादी और नौकरी का झांसा देकर एक युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में चकेरी पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शुक्रवार शाम 4:40 बजे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, उन्नाव की रहने वाली पीड़िता नोएडा में कार्यरत है।

शिव मंदिरों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करें

बाराबंकी डीएम ने अफसरों को दिए निर्देश, पिछले साल अवसानेश्वर मंदिर में हुआ था हादसा

■ डीएम ने अवसानेश्वर मंदिर में हुए हादसे से सबक लेने को कहा।

तमसा संकेत, एजेंसी

बाराबंकी। सावन मास और श्रावण मेले के दौरान शिव मंदिरों एवं मेला स्थलों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बाराबंकी जिला प्रशासन ने विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट स्थित लोकसभा-गार में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को मंदिरों, मेला स्थलों और अस्थायी दुकानों पर बिजली से जुड़े सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी ने लोधेश्वर महादेवा और अवसाने-श्वर महादेव मंदिर समेत जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में लगे बिजली के खंभों को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खंभों को आवश्यक ऊंचाई तक प्लास्टिक या अन्य उपयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री से ढका जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का विद्युत हादसा न हो। इसके साथ ही खंभों के आसपास जलभराव रोकने के लिए गड्ढों को भरने और अन्य जरूरी इंतजाम समय से पूरे करने को कहा गया। डीएम ने श्रावण मेले के दौरान लगने वाली सभी अस्थायी दुकानों का अनिवार्य विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में अधीक्षण अभियंता भविष्य कुमार, अधिशासी अभियंता घनश्याम त्रिपाठी सहित विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सावन मेले के दौरान निर्बाध और सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

मानसून में 24 घंटे अलर्ट रहेंगी बिजली विभाग की टीमें

मानसून के दौरान संभावित लाइन फॉल्ट और तकनीकी खराबियों को देखते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की टीमों को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि आम जनता और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जर्जर तारों और खंभों की होगी नियमित जांच

डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि जिले में जर्जर बिजली तारों और पुराने खंभों की नियमित जांच की जाए। जहां भी मरम्मत या बदलाव की आवश्यकता हो, वहां समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा किया जाए, ताकि बरसात के मौसम में किसी प्रकार की दुर्घटना या बिजली बाधित होने की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने गलत बिलिंग और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

वकीलों ने फाड़ी अधिवक्ता संशोधन बिल की प्रतियां

कानपुर में किया विरोध प्रदर्शन, कहा- बिल में सुरक्षा

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में शुक्रवार को वकीलों ने शताब्दी गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बिल की प्रतियां फाड़ी। अधिवक्ता संसोधन बिल वापस लो... के नारे लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का यह बिल अधिवक्ता विरोधी है। बिल में अधिवक्ताओं की सुरक्षा, बीमा और पेंशन जैसे कोई मुद्दे को प्रमुखता नहीं दी गई है।

विदेशी अधिवक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में भाग लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह विदेशी अधिवक्ताओं को भारत में प्रवेश की शुरुआत होगी। अधिवक्ता को दो साल या उससे अधिक की सजा पर

उसका लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है, भरकम पंजीकरण शुल्क से सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के होनहार और बुद्धिमान बच्चे वकालत करने से वंचित हो जाएंगे।

पंजीकरण शुल्क 750 से बढ़कर 22500 प्रस्तावित

अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के तत्वावधान में कानपुर कचहरी के शताब्दी गेट पर अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 पर वकीलों ने विरोध जताया। बगैर सुरक्षा, बीमा, इलाज और पेंशन के संसोधन विधेयक वापस लो... की तख्तियां लेकर वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और बिल की प्रतियां फाड़ी। समिति के संयोजक व पूर्व लॉयर्स अध्यक्ष पं. रवींद्र शर्मा ने बताया कि पंजीकरण शुल्क 750 से बढ़कर 22500 रुपए प्रस्तावित है। इसमें 18 हजार रुपये राज्य विधिज्ञ परिषद और 4500 रुपये बार काउंसिल आफ इंडिया का होगा।

किसी ने दौड़ लगाई तो किसी ने ढपली बजाई, बोले- छात्रों की आवाज दबाने के बजाए सुनी जाए

सत्याग्रह के बाद सपा विधायकों ने दिया ज्ञापन

विरोध

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। NEET पेपर लीक, दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को सत्याग्रह से पहले गुरुवार को हाउस अरेस्ट किया गया। आवस पर ही छात्रसंघ के बैनर तले विधायक 24 घंटे सत्याग्रह पर बैठ गए। शुक्रवार दोपहर 12.30 उन्होंने धरना समाप्त किया। सत्याग्रह खत्म होने के बाद विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ढपली बजाकर विरोध जताया इस दौरान वहां ज्ञापन देने पूर्व सांसद सुभाषिनी अली भी पहुंची। सत्याग्रह समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन

एडीसीपी अर्चना सिंह को सौंपा। ज्ञापन में नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग की गई। अमिताभ बाजपेई ने कहा कि देश का युवा केवल निष्पक्ष परीक्षा, समान अवसर और न्याय की मांग कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठना लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने वाले छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। जंतर-मंतर पर बल प्रयोग के

बड़ी संख्या में छात्र और सपाई नेता रहे मौजूद

सत्याग्रह में पूर्व सांसद सुभाषिनी अली, पूर्व मेयर प्रत्याशी वंदना बाजपेई, दीपा यादव, नीरज सिंह, वरुण मिश्रा, कुतुबुद्दीन मंसूरी, राजीव शर्मा, मोइन खान, सर्वेश यादव, कुलदीप यादव, विनय कोरी, कृपा शंकर त्रिवेदी, संतोष पांडे, चंकी गुप्ता, पार्षद रजत बाजपेई सहित में छात्रसंघ के पूर्व पदाधिकारी, युवा, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक शामिल हुए। कानपुर की कैंट विधानसभा से सपा विधायक हसन रूमी का 24 घंटे का सत्याग्रह शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे समाप्त हो गया। गुरुवार को पुलिस की रोका था, उन्होंने अपने आवास के बाहर ही सत्याग्रह शुरू किया था। सत्याग्रह खत्म होने के बाद विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ढपली बजाकर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कैंट एसीपी प्रियंका बाजपेई को सौंपा।

मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। पेपर लीक के कारण मानसिक तनाव में आत्महत्या करने वाले छात्र-छात्राओं के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी मदद दी जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई।

राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि नीट पेपर लीक से देश की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा टूटा है। साथ ही जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

- सपा विधायक हसन रूमी सत्याग्रह के दौरान ढपली बजाते हुए।
- सपा विधायक के सत्याग्रह समापन में पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने ज्ञापन दिया।

ज्ञापन में रखीं ये प्रमुख मांगें

ज्ञापन में मांग की गई कि नीट पेपर लीक की समयबद्ध और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए।

काशी में रेलवे अफसर को सीबीआई पकड़कर ले गई

वाराणसी। यूपी के वाराणसी में CBI ने रेलवे के एक सीनियर अफसर को छापेमारी कर पकड़ा है। उन पर फर्नीचर कारोबारी से बिल पास करने के लिए 1.70 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। कारोबारी की शिकायत पर गुरुवार शाम CBI ने DRM ऑफिस और अफसर के आवास पर एक साथ छापेमारी की। टीम ने परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों से पूछताछ की। CBI ने आरोपी अफसर नितेश अग्रवाल को हिरासत में ले लिया। उनका मोबाइल, लैपटॉप और कुछ फाइलों को भी कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि उनके घर से कुछ रुपयों की बरामदगी भी हुई है। नितेश बनारस रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक (सीनियर DMM) हैं। वह यहां 3 साल से तैनात थे। नीतेश अग्रवाल के पास पूरे मंडल के रेलवे कर्मचारियों को ड्रेस-जूते आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा, आवश्यक उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स और अन्य जरूरी सामान की स्थानीय स्तर पर खरीद जैसी जिम्मेदारी थी।

आरोप : कहती है कि तेरी जैसी मेरे यहां झाड़ू लगाती हैं, केंद्रीय विद्यालय का मामला

टीचर इंग्लिश में गालियां देती हैं : छात्रा

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर में 12वीं की एक छात्रा ने अपनी इंग्लिश टीचर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि पिछले 1 साल से केंद्रीय विद्यालय की टीचर लगातार उसे निशाना बना रही थीं। कभी पूरी क्लास के सामने डांटती थीं, तो कभी करेक्टर को लेकर अपमानजनक बातें कहती थीं। इंग्लिश में गालियां देती थी। इतना ही नहीं कहती थी कि तेरी जैसी मेरे यहां झाड़ू लगाती हैं। रोज-रोज सबके सामने बेइज्जत किए जाने से छात्रा मानसिक रूप से टूट गई और डिप्रेशन में चली गई। हालत ऐसी हो गई कि उसने स्कूल जाना भी कम कर दिया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार रात करीब 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हालांकि, छात्रा और उसके परिजन एफआईआर मेंलगाई गई धाराओं से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि शिकायत में जिन गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया था, उनके मुताबिक धाराएं नहीं लगाई गई हैं। मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है। नौबस्ता थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा ने बताया- मैं क्लास-1 से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रही हूं। इस बार 12वीं में हूं। 11वीं से टीचर सुभाना भामर हमें इंग्लिश पढ़ा रही हैं। इसी दौरान उन्होंने मेरे चरित्र पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। वह स्टाफ रूम में भी मेरे चरित्र को लेकर गलत बातें करती थीं।

इतना ही नहीं, पूरी क्लास के सामने मेरी जाति को

■ **पीड़िता के चाचा ने बताया कि टीचर की लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर उनकी भतीजी ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया।**

लेकर भी अपमानित करती थीं। मैंने एक बार विरोध किया तो फेल करने की धमकी दी। वह कहती थीं, 'तेरे जैसी मेरे यहां झाड़ू लगाती थी, तू भी एक दिन मेरे यहां झाड़ू लगाएगी।' छात्रा का कहना है कि टीचर हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उसे ही नहीं बल्कि दूसरे छात्रों को भी गालियां देती थीं। इससे वह काफी परेशान रहने लगी थी। फेल होने के डर से वह रोज स्कूल जाती रही। जुलाई में स्कूल खुलने के बाद भी टीचर का व्यवहार नहीं बदला। इसके बाद उसने 18 जुलाई से स्कूल जाना बंद कर दिया। छात्रा ने बताया- 18 जुलाई से मैं लगातार चकेरी थाने के चक्कर लगा रही थी। कई दिन बाद 23 जुलाई की रात मेरी एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं, उनसे न मैं संतुष्ट हूं और न ही मेरा परिवार। जिन बातों की शिकायत मैंने की थी, उनके हिसाब से धाराएं नहीं लगाई गई हैं। छात्रा का कहना है कि उसने इन्हीं आरोपों को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब एफआईआर हुई भी है तो उसमें सभी जरूरी धाराएं नहीं लगाई गई हैं। इसलिए परिवार की मांग है कि जातिसूचक टिप्पणी, चरित्र हनन और अन्य आरोपों के आधार पर उचित धाराएं बढ़ाई जाएं और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़िता के चाचा ने बताया- मेरी 17 साल की भतीजी को टीचर लगातार अपमानित करती थीं। वह जातिसूचक टिप्पणियां करती थीं, मानसिक दबाव बनाती थीं और विरोध करने पर कानूनी कार्रवाई में फंसाने की धमकी देती थीं। लगातार प्रताड़ना के कारण उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई और उसने स्कूल जाने से भी कतराना शुरू कर दिया। आरोपी टीचर सुभावना भामा के पति मनीष कुमार ने कहा- 18 जुलाई को स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी का इंटरव्यू चल रहा था। वहां 11 टीचर इंटरव्यू ले रहे थे। इसी दौरान मेरी पत्नी ने छात्रा से कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह उनका जवाब नहीं दे पाई और इंटरव्यू में फेल हो गई। इसके बाद से वह मेरी पत्नी पर झूठे आरोप लगा रही है।

कानपुर के व्यापारियों ने डीएम के सामने उठाईं समस्याएं

वाहन टैगिंग वापस लेने और बिजली के तार अंडरग्राउंड करने की मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर के बाजारों से जुड़ी सड़क, जलभराव, सीवर, बिजली और यातायात समेत कई समस्याएं उठाई गईं। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि शहर के अलग-अलग बाजारों के व्यापारियों ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मंडी परिषद की ओर से लागू की गई नई वाहन टैगिंग व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका

है। इस मामले को लखनऊ स्तर तक उठाया गया है और इसे वापस लेने की मांग की गई है। उन्होंने साल 2023 में कोपरगंज बाजार में खुले बिजली के तारों के कारण हुए भीषण अग्निकांड का मुद्दा भी उठाया। व्यापार मंडल ने मांग रखी कि बाजारों में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड कराया जाए। ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी पहले भी इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं और इस बैठक में भी उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। बैठक में किदवई नगर और यशोदा नगर बाजार में सीएम ग्रिड परियोजना के कारण व्यापारियों को हो रही परेशानियों का मुद्दा भी उठाया गया। व्यापार मंडल ने परियोजना का कार्य तेजी से पूरा कराने की मांग की, ताकि कारोबार प्रभावित न हो। बैठक में विभिन्न व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव जिलाधिकारी के सामने रखे।

कांवड़ मेले के लिए रेलवे की तैयारी

हरिद्वार तक बढ़ेंगी कईं ट्रेनें, 4 जोड़ी मेला स्पेशल भी चलेंगी

योजना

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद। सावन कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने विशेष रेल संचालन योजना लागू की है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनों का विस्तार किया जाएगा। साथ ही चार जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।

रेलवे ने 30 जुलाई से 29 अगस्त तक चार जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। इनमें हरिद्वार–दिल्ली शाहदरा (04314/04313), योग नगरी

ऋषिकेश–दिल्ली शाहदरा (04316/04315) और योग नगरी ऋषिकेश–आलमनगर स्पेशल एक्सप्रेस समेत अन्य विशेष ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के संचालन से मेले के दौरान अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यात्रियों की सहायता के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे।

> श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सहारनपुर, रायवाला, मोतीचूर, ज्वालापुर और कांगड़ी स्टेशनों पर कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। इनमें देहरादूनझसूबेदारगंज लिंक एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलकझयोग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, ओखाझदेहरादून एक्सप्रेस और हेमकुंड एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं।

दिल्ली से हरिद्वार तक बढ़ेगा ट्रेनों का संचालन

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, 30 जुलाई से 28 अगस्त तक दिल्ली-शामली-दिल्ली पैसेंजर (74022/74023) और दिल्ली-सहारनपुर-दिल्ली मेमू ट्रेन का संचालन हरिद्वार तक किया जाएगा। इससे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सफर करने वाले कांवड़ियों को राहत मिलेगी।

डीआरएम ने दिए बेहतर व्यवस्था के निर्देश

मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।

सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे।

गोरखपुर में निलंबित क्लर्क ने ऑफिस में हमला किया, बोला- पिस्तौल निकालो

निरीक्षण करने पहुंचे अफसर को थप्पड़ मारे

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर के सिंचाई विभाग के कार्यालय में इंजीनियर की पिटाई कर दी गई। वह कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी बीच, निलंबित क्लर्क, सहायक अभियंता और एक युवक वहां पहुंच गए। तीनों ने उन्हें घेर लिया और थप्पड़ बरसाए। इस दौरान निलंबित क्लर्क ने कहा, पिस्तौल निकालो, आज इसी को मार देते हैं। इसे छोड़ूंगा नहीं। करीब 20 मिनट तक कार्यालय में मारपीट-हंगामा चलता रहा। वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। घटना गुरुवार दोपहर 1 बजे की है, इसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया। पीड़ित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा- विभागीय जांच के बाद उनकी रिपोर्ट पर क्लर्क को

निलंबित कर दिया था। उसका वेतन भी रोक दिया गया था। इसी रंजिश से उसने उन पर हमला किया। पुलिस ने इंजीनियर की शिकायत पर 2 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर विकास सिंह और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विपिन सिंह गुरुवार दोपहर कैंट थाना क्षेत्र स्थित बाढ़ खंड कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया, मैं निरीक्षण कर रहा था।

> विपिन सिंह ने बताया कि जनवरी और अप्रैल में भी क्लर्क दीपक पांडेय ने एक कर्मचारी के जरिए उन्हें घर से उठवा लेने की धमकी दी थी। इसके बाद उन्होंने एसएसपी, डीएम और कमिश्नर से शिकायत की। विभागीय जांच के बाद 30 अप्रैल को दीपक पांडेय को निलंबित कर दिया गया। उसका वेतन भी रोक दिया गया था।

फास्ट न्यूज

खेत में लगी समर की कोठरी से चोरी

मथुरा। गुरुवार बीती रात राया थाना क्षेत्र के थोक ग्यान गांव में एक खेत से चोरी की घटना सामने आई है। अज्ञात चोरों ने खेत में लगे ट्यूबवेल की कोठरी का कुंडा तोड़कर करीब 40 मीटर बिजली केबिल, एक फावड़ा और एक चादर चुरा ली। गांव थोक ग्यान निवासी इशाक मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने रात करीब दस बजे तक अपने खेत में पानी लगाया था। अगली सुबह जब वे खेत पर पहुंचे, तो देखा कि कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और उसका कुंडा टूटा हुआ था।

बंधक जमीन फर्जी दस्तावेजों से बेचने का आरोप

सुलतानपुर। सुल्तानपुर में फाइनेंस कंपनी से लिए गए 2 लाख रुपये के व्यापारिक ऋण की अदायगी न करने और बंधक रखी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने के आरोप में एक महिला के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

श्री राम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक अरसद अहमद के अनुसार, लंभुआ क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव निवासी सावित्री देवी ने 30 जनवरी 2020 को कंपनी से 2 लाख रुपये का व्यापारिक ऋण लिया था। ऋण की अंतिम किस्त 5 फरवरी 2024 तक जमा करनी थी।

बरौला गांव में 'हर घर जल' योजना सुस्त

सुलतानपुर। सुलतानपुर के कूरेभार विकास खंड के बरौला गांव में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 'हर घर जल' अभियान की रफ्तार धीमी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण करोड़ों रुपये की यह पेयजल परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। इससे ग्रामीणों को नल से शुद्ध पेयजल मिलने का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है।

पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट

कई लोगों की मौत की आशंका, राहत-बचाव जारी

तमसा संकेत, एजेंसी

सहारनपुर। जिले के गंगोह थाना क्षेत्र स्थित नया गांव में शुक्रवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि उसकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे में कई लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कई अन्य के घायल होने की सूचना है। हालांकि, प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों की आधिकारिक संख्या अभी जारी नहीं की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विस्फोट के तुरंत बाद फैक्ट्री में आग लग गई। तेज धमाके के कारण फैक्ट्री का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास के

लोगों ने आग की लपटें और धुएं का गुबार उठते देखा, जिसके बाद इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण सबसे पहले मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य में प्रशासन का भी सहयोग किया।

पीएनबी मैनेजर से 2.20 करोड़ ठगी, केस दर्ज

प्लॉट देने के नाम पर रुपए लिए, बैनामा नहीं कराया, रुपए मांगे तो तमंचा ताना

तमसा संकेत, एजेंसी

आगरा। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के प्रबंधक दंपती से प्लॉट बेचने के नाम पर 2.20 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर थाना जगदीशपुरा पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि बैनामे के दिन विक्रेता पक्ष नहीं पहुंचा और बाद में रकम लौटाने से इनकार करते हुए एक करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की मांग की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार, ओल्ड ईदगाह कॉलोनी निवासी शिंकी हांडा ने शिकायत में बताया कि वह और उनके पति पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक हैं। उन्होंने सेक्टर-1 निवासी प्रहलाद कुमार प्रजापति और भीकम सिंह से 305 वर्गमीटर का प्लॉट 2.20 करोड़

रुपये में खरीदने का समझौता किया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 10 जुलाई को तहसील में बैनामा होना तय था, लेकिन विक्रेता पक्ष वहां नहीं पहुंचा। फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने न तो बैनामा किया और न ही रकम लौटाने को तैयार हुए। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने फर्जी जन सेवा केंद्र खोल रखा था। साइबर ठगी से हासिल रकम ई-वॉलेट में मंगाई जाती थी और उसी पैसे से बिजली व मोबाइल बिल जमा कराने के साथ ट्रेन और हवाई टिकट बुक कराए जाते थे, ताकि रकम का स्रोत छिपाया जा सके।

डिमांड ड्राफ्ट और स्टांप शुल्क समेत पूरी रकम की व्यवस्था

शिकायत के मुताबिक, सौदे के तहत 10 लाख रुपये नकद और चेक के माध्यम से दिए गए। प्लॉट एक फाइनेंस कंपनी में बंधक होने के कारण उसे मुक्त कराने के लिए 29 मई को 99-99 लाख रुपये के दो डिमांड ड्राफ्ट फाइनेंस कंपनी के नाम जारी कराए गए। इसके अलावा 8 लाख रुपये और दिए गए तथा 14.40 लाख रुपये स्टांप शुल्क के रूप में जमा कराए गए।

साइबर ठगी का आरोपी नाम बदलकर दो साल तक बचता रहा

इधर, आगरा पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी आशीष वशिष्ठ के बारे में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, उसने दो साल पहले राजपत्र के जरिए अपना नाम बदलकर आरव वशिष्ठ कर लिया था और इसी नाम से नया आधार कार्ड भी बनवा लिया था। पुलिस का कहना है कि इसी वजह से वह लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचा रहा।

तमंचा दिखाकर धमकाने और अतिरिक्त रकम मांगने का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि जब दंपती आरोपियों के घर पहुंचे तो उनके साथ गाली-गलौज की गई। आरोप है कि आरोपी के बेटे ने तमंचा दिखाकर धमकाया और प्लॉट का बैनामा करने के लिए एक करोड़ रुपये अतिरिक्त देने की मांग की।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ले-आउट तैयार, रेरा पंजीकरण का इंतजार, 1980 से था जमीन पर विवाद

मदरसा तोड़कर खाली कराई जमीन पर आवासीय योजना बनाएगा एमडीए

तमसा संकेत, एजेंसी

मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने करीब दो महीने पहले खाली कराई गई जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसे की जमीन पर आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने परियोजना का ले-आउट तैयार कर रेरा पंजीकरण के लिए भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद योजना को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इस भूमि को लेकर लगभग 50 वर्षों से विवाद चल रहा था। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने करीब डेढ़ दशक पहले सुप्रीम कोर्ट में भी अपने पक्ष में फैसला हासिल कर लिया था। इसके बावजूद विभिन्न कानूनी और तकनीकी कारणों से

प्राधिकरण को जमीन का कब्जा नहीं मिल पा रहा था। एमडीए के अनुसार, मझोला थाना क्षेत्र के मंगूपुरा में स्थित इस जमीन पर उसका स्वामित्व है, नेशनल हाईवे किनारे करीब 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसे को 9 मई को जिला प्रशासन और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर हटाया गया था। प्रशासन का कहना था कि यह जमीन सरकारी है और इस पर लंबे समय से कब्जा था। लेकिन मदरसा कमेटी लंबे समय तक कब्जा बनाए रही। प्राधिकरण का दावा है कि स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला उसके पक्ष में आने के बाद भी जमीन का कब्जा नहीं सौंपा गया।

9 मई को संयुक्त अभियान में हटाया गया था मदरसा

नेशनल हाईवे किनारे करीब 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर बने जामिया अरबिया हयातुल उलूम मदरसे को 9 मई को जिला प्रशासन और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई में बुलडोजर चलाकर हटाया गया था। प्रशासन का कहना था कि यह जमीन सरकारी है और इस पर लंबे समय से कब्जा था।

> एमडीए के उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि खाली कराई गई भूमि पर आवासीय परियोजना का ले-आउट तैयार कर रेरा पंजीकरण के लिए भेज दिया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई आवासीय योजना को सार्वजनिक किया जाएगा।

बस ने पति-पत्नी को कुचला

बेटा गंभीर घायल, सड़क पार करते समय हादसा

मौत

तमसा संकेत, संवाददाता

मथुरा। मथुरा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पति-पत्नी और उनकी नातिन को कुचल दिया। हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी नातिन गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा इतना भीषण था कि पति-पत्नी का सिर बुरी तरह कुचल गया और दोनों के शव सड़क पर पड़े रहे। पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे दंपती अपनी नातिन के साथ आगरा-दिल्ली नेशनल हाईवे पर नवादा चौराहे के पास खड़े थे। इसी बीच तेज रफ्तार मथुरा डिपो की रोडवेज बस ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद बस चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों

- महिला का सिर बुरी तरह कुचल गया था। मौके पर मौजूद लोगों ने शव को ढकने के लिए उसके सिर पर कपड़ा डाल दिया।
- बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद युवक कई मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया।

की भीड़ जुट गई, जिससे हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल नातिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान फरह थाना क्षेत्र के बेरी गांव निवासी मूलचंद उर्फ मूली (60) और उनकी पत्नी मंजू देवी (58) के रूप में हुई है। दोनों शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे अपनी नातिन मीना पुत्री कप्तान के साथ पैरों के दर्द की दवा लेने नवादा आए थे। दवा लेकर वापस घर लौटते समय वे हाईवे किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी आगरा की ओर से आ रही मथुरा डिपो की तेज रफ्तार रोडवेज बस ने तीनों को कुचल दिया। हादसे में मूलचंद और मंजू देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी नातिन मीना घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मृतक दंपती मथुरा के बेरी गांव के रहने वाले थे।

पृष्ठ 01 का शेष...

पेपर लीक केस ...

जबकि विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय सचिव बना दिया गया है। इसके अलावा 1995 बैच के IAS अधिकारी टी.के. अनिल कुमार को पदोन्नत कर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

धर्मेंद्र प्रधान ...

इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 100 से ज्यादा छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साहिल इनमें से एक है। राहुल ने जिस छात्र की चोट दिखाई। उसका नाम साहिल लोचाब है। वह 19 साल का है और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की पैलेट गन से इनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। AIIMS के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी हुई है। परिवार के मुताबिक, डॉक्टरों ने बताया है कि घायल आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। साहिल दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) के छात्र हैं। उनकी मां ज्योति ने बताया, 'वह पहले भी CJP के प्रदर्शन में गया था। सोमवार को भी यह कहकर गया कि यह उसके लिए जरूरी है और उसकी पढ़ाई से जुड़ा मुद्दा है। वह हमेशा पुलिस अधिकारी बनना चाहता था।' केंद्र ने संसद में बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आय 2019-20 में 504 करोड़ थी,जो 2023-24 में बढ़कर 1,116 करोड़ हो गई। इसी दौरान खर्च 440 करोड़ से बढ़कर 1,040 करोड़ पहुंच गया। सरकार ने बताया कि 2018 में बनने के बाद NTA ने 270 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित कीं, जिनमें 6.6 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। 2026 में अब तक 12 परीक्षाएं कराई गई हैं, जिनमें 65 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। NTA में 39 स्थायी पद हैं। इसके अलावा 73 संविदा और 124 आउटसोर्स कर्मचारी भी काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 'वंदे मातरम्' के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है। राहुल गांधी ने कहा, जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाता, हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। रिजिजू ने बयान दिया कि वह हमारे सांसदों को बताना चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ₹क्या विपक्ष सांसद होने की जिम्मेदारी निभा रहा है? अगर उनके पास मुद्दे हैं तो वे संसद में आकर चर्चा करें। प्रधानमंत्री भी चर्चा की बात कह चुके हैं और सरकार भी बहस के लिए तैयार है। फिर विपक्ष सदन से बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहा है? सामान्य नियम यह है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है, तो उसका जवाब दिया जाता है। जब मैं जवाब देना चाहता था, तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझे मौका नहीं दिया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने कल फैसला किया कि पेपर लीक से जुड़े जो मामले अदालतों में लंबित हैं, उनकी सुनवाई के लिए खास तौर पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। ये कोर्ट रोजाना सुनवाई करेंगे, तेजी से ट्रायल करेंगे और तय समय में जांच पूरी करेंगे ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। यह एक बड़ा फैसला है। पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा- ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वे असलियत से दूर हो गए हैं। उनके आस-पास के लोग भी उन्हें यह नहीं समझा पा रहे हैं कि छात्र और युवा क्या चाहते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो आपकी सत्ता चली जाएगी।भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा- क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी या उसकी किसी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? लोग उनसे नहीं जुड़ रहे थे और वे 100 चुनाव हार चुके हैं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। उस भूख हड़ताल के आस-पास जमा हुए लोगों और देश भर में मिल रही प्रतिक्रिया को देखते हुए, कांग्रेस ने इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। सदन में हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा में लगातार पांचवें दिन कार्यवाही नहीं चल सकी। नीट पेपर लीक हंगामे के बीच लोकसभा 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी।

प्रधान के इस्तीफे ...

उन्होंने कहा कि जब इस जांच-पड़ताल से तथ्य सामने आ जाएंगे, तब आदेश दिया जाएगा। RAF ने सोशल मीडिया पर मौजूद कई वीडियो और तस्वीरों को जांच के लिए भेजा है। इनमें नीले रंग की वर्दी (डांगरी) पहने जवान दिखाई दे रहे हैं। इनमें ऐसे फुटेज शामिल हैं जिनमें वे बंदूकें और लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं। साथ ही ऐसे वीडियो भी हैं जिनमें भीड़ ने उनके जवानों को घेरकर उन पर हमला किया था। CJP प्रोटेस्ट के दौरान लाठीचार्ज को लेकर दिल्ली पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, इस सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देवेश कुमार श्रीवास्तव ने को बताया है कि CJP प्रोटेस्ट को लेकर किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा- किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी को सस्पेंड करने या विभागीय कार्रवाई करने की सोशल मीडिया पर आई खबर गलत है। पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कानून के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा जितने पुलिस अधिकारी घायल हुए थे उनमें ज्यादातर को अब अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उनकी अब ड्यूटी भी लगाई जा रही है। रिपोर्टर ने शाम को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट लीडर अभिजीत दीपके से बात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुकी सरकार के दवाब में हैं। इस पर अभिजीत ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा रखी थी इस देश को जागरूक करने के लिए। वे हमारे ही साथ हैं। को स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए सैकड़ों फुटेज की जांच की गई। जिसमें हमें 15 थानों की जिला पुलिस से 216 क्रिमिनल की पहचान की गई। दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बताया कि अभी तक कुल 15 FIR दर्ज हुई हैं। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 65 स्टूडेंट घायल हुए। इनके अलावा 130 लोग अन्य घायल हैं। अभी भी प्रोटेस्ट साइट पर करीब 10 से 12 हजार लोग हैं। कुल 3000 से ज्यादा पुलिस की तैनाती है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में NEET पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। बनर्जी छात्रों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए विरोध स्थल पर जाएंगी। कोलकाता में तृणमूल की सालाना 21 जुलाई 'शहीद दिवस' रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राष्ट्रीय राजधानी में CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा- अगर जरूरत पड़ी तो मैं दिल्ली जाऊंगी और CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होऊंगी। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेतृत्व में NEET पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। बनर्जी छात्रों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए विरोध स्थल पर जाएंगी। कोलकाता में तृणमूल की सालाना 21 जुलाई 'शहीद दिवस' रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राष्ट्रीय राजधानी में CJP के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

सीएम के पैर छुए, सम्राट बोले- अगले आईपीएल ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी, 19 खिलाड़ियों को जॉइनिंग लेटर

क्रिकेटर आकाशदीप, मुकेश कुमार बने डीएसपी

नियुक्ति

पटना, एजेंसी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीतने वाले 19 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर दिया।

इनमें भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और एथलेटिक्स खिलाड़ी पीयूष राज को पुलिस अवर निरीक्षक (ASI) पद पर नियुक्ति दी गई।

वहीं आकाशदीप और मुकेश कुमार ने पैर छूकर मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया।

ऊर्जा ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का आयोजन किया गया।

इस साल 106 खिलाड़ियों को लेटर पहले ही दिए जा चुका है। इस योजना में नियुक्ति-पत्र, खेल छात्रवृत्ति चयन-पत्र और खेल सम्मान राशि दी गई। सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि 15 सितंबर के बाद बिहार के सभी पंचायत में स्पोर्ट्स को लेकर टैलेंट की खोज की जाएगी।यह अभियान 6 महीने तक चलेगा। पूरे प्रदेश में जो भी खिलाड़ी मिलेगा, उसे प्रशिक्षित करके देश के लिए तैयार करने का काम किया जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने आगे कहा- आने वाले IPL ऑक्शन में बिहार की टीम भी रहेगी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रवीन्द्रण शंकरण ने बताया, राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सीधी नियुक्ति देकर खेल छात्रवृत्ति उपलब्ध कराकर उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

सेतु मिश्रा को 37.50 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई

एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2026 में स्वर्ण और रजत पदक जीतने और एथलेटिक्स में अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी बने सेतु मिश्रा को 37.50 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई।

19 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र मिला है

इसके अलावा समारोह के दौरान 5 पैरा खिलाड़ियों सहित विभिन्न खेल विधाओं के बाकी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी नियुक्ति-पत्र सौंपे गए।

मुख्यमंत्री ने सेतु मिश्रा को सौंपा 37 .50 लाख रुपये का चेक।

> इसी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभास्कर कुमार को 2 लाख रुपये की सम्मान राशि दी गई। कॉमनवेल्थ यूथ शतरंज चैंपियनशिप-2026 की ब्लिट्ज स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली मरियम फातिमा को 9 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना-2026

- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, पोषण, खेल सामग्री, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और खेल विज्ञान संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती
- हर साल 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है
- अभी के वित्तीय वर्ष में 637 खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति चयन-पत्र प्रदान किए जाएंगे
- उत्कर्ष योजना के 21, सक्षम योजना के 184, प्रेरणा योजना के 432 खिलाड़ी शामिल हैं
- प्रेरणा योजना में चयनित 432 खिलाड़ियों में से 269 खिलाड़ियों का चयन राज्यव्यापी 'मशाल प्रतिभा खोज कार्यक्रम' के जरिए हुआ है

मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर भारतीय दल की अगुआई की

कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी किंग चार्ल्स ने किया उद्घाटन

ग्लासगो, एजेंसी

कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुई। ओवो हाइड्रो एरिना में दो बार की ओलिंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और टोक्यो ओलिंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने तिरंगा लेकर 125 सदस्यीय भारतीय दल की अगुआई की।

ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने खेलों का उद्घाटन किया। इसके बाद भारत समेत 74 देशों के खिलाड़ियों ने मार्च-पास्ट में हिस्सा लिया।

भारत के लिए खेलों की शुरुआत भी शानदार रही। उद्घाटन समारोह से पहले ही भारतीय खिलाड़ियों ने लॉन बॉल्स में दो जीत दर्ज कर विजयी आगाज किया। पुतुल सोनोवाल ने वर्ल्ड चैम्पियन कनाडा के रेयान बेस्टर को मात दे दी।

महिला डबल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी ने भी अपना पहला मैच जीता। भारतीय जोड़ी ने 'ग्रुप बी' के मैच में माल्टा की रिक्कसन बहनों (रेबेका लुईस और कोनी-लेघ) को टाईब्रेकर में हराया।

वहीं भारतीय ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहेन महिला 75 किलोग्राम वर्ग में सीधे सेमीफाइनल में पहुंचने के कारण बिना मुकाबला खेले ही कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर चुकी हैं। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत स्कॉटलैंड की संस्कृति, इतिहास और विरासत के विशेष वीडियो से हुई। इसके बाद किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला एरिना पहुंचे। उनके साथ प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम भी मौजूद रहे। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रगान 'गॉड सेव अवर किंग' प्रस्तुत किया गया और फिर एक-एक कर सभी 74 देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने मार्च-पास्ट किया। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले इन खेलों में भारत 125 खिलाड़ियों का दल भेजा है। ओपनिंग सेरेमनी ग्लासगो के ओवो हाइड्रो एरिना में हुई, जहां करीब 13 हजार दर्शक मौजूद रहे। भारतीय दल इस बार एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वेटलिफ्टिंग, लॉन बॉल्स समेत 10 खेलों में चुनौती पेश करेगा।

ऑस्ट्रेलिया सीईओ बोले-भारत बड़ा मार्केट, संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले शेड्यूल व्यस्त होना बड़ी चुनौती

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड टेस्ट मैच भारत में कराने पर विचार

नई दिल्ली, एजेंसी

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा है कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भारत में टेस्ट मैच कराने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार में क्रिकेट के लिए बड़े मौके हैं, हालांकि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस साल दिसंबर में पहली बार बिग बैश लीग (BBL) का ओपनिंग मैच भारत में कराएगा। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इसी तरह भविष्य में भारत में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रदर्शनी टेस्ट कराने की संभावना भी देखी जा रही है।

ऑस्ट्रेलिया में खेली गई पिछली एशेज सीरीज में कंगारू टीम ने इंग्लैंड को 4-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) की हालिया वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के खिलाफ सीरीज बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सीरीज में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ECB की आय काफी हद तक भारत जैसी बड़ी ब्रॉडकास्ट सीरीज पर निर्भर करती है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, 2027 में पुरुष और महिला एशेज की मेजबानी के बावजूद बोर्ड को घाटे की आशंका है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अगली एशेज सीरीज 2027 में इंग्लैंड में खेली जाएगी। इससे पहले मार्च 2027 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर दोनों टीमों के पहले टेस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर डे-नाइट (पिंक बॉल) टेस्ट खेला जाएगा। यह मुकाबला एशेज सीरीज का हिस्सा नहीं होगा।

भारत में नए क्रिकेट कंटेंट की संभावना

बीबीसी के 'स्टंप्ड' पॉडकास्ट में ग्रीनबर्ग ने कहा, 'हमें सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ECB और BCCI दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। भारत में क्रिकेट का नया कंटेंट ले जाने के मौके हैं। अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है।'

उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट मजबूत स्थिति में है और इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का व्यस्त कैलेंडर सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रीनबर्ग ने कहा, 'साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं। जितना क्रिकेट और कंटेंट हम देना चाहते हैं, उसके लिए शायद एक-दो महीने और चाहिए।'

मनोरंजन

कमल हासन बोले- सिस्टम सड़ चुका है, इमरान और वरुण समेत कई एक्टर्स समर्थन में उतरे

छात्रों की बात सुनना अहसान नहीं, हमारा फर्ज : करीना

नई दिल्ली। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे नीट पेपर लीक और शिक्षा सुधार आंदोलन को अब बॉलीवुड हस्तियों का बड़ा समर्थन मिल रहा है। सलमान खान, आलिया भट्ट और अनन्या पांडे के बाद अब करीना कपूर खान, कमल हासन, वरुण धवन, इमरान खान और पीयूष मिश्रा भी छात्रों के पक्ष में आ गए हैं। करीना कपूर ने कहा कि देश के युवाओं की मांग सुनना कोई अहसान नहीं, बल्कि हमारा फर्ज है। वहीं कमल हासन ने मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को सड़ा हुआ बताया है। इमरान खान ने मुंबई में खुद सड़क पर उतरकर छात्रों के साथ प्रदर्शन किया। एक्टर इमरान खान बुधवार को नीट धांधली के खिलाफ मुंबई में आयोजित एक विरोध मार्च में खुद शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में 'चलो संसद' मार्च के दौरान छात्रों पर हुए आंसू गैस और लाठीचार्ज पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने लिखा था, जब मैंने देखा कि पुलिस छात्रों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज कर रही है, तो मेरा दिल टूट गया। जिन छात्रों ने मेहनत की, उन्हें सिस्टम ने धोखा दिया और जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाही तो उन्हें लाठियों से चुप करा दिया गया।

इमरान खान मुंबई प्रोटेस्ट में शामिल हुए।

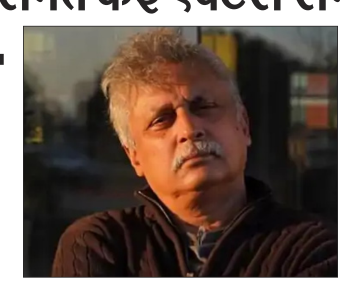

करीना बोलीं- बच्चे कल की तैयारी नहीं कर रहे, वे ही कल हैं

करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया है। उन्होंने लिखा, मैं पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर शांत थी, लेकिन अब चुप नहीं रह सकती। अपनी आवाज उठाने वाले युवाओं की अनदेखी करना नामुमकिन है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा से बच्चे को भरोसा और उम्मीद मिलती है। लेकिन शिक्षा तभी काम करती है जब बच्चों को इस पर विश्वास हो। अगर उन्हें लगेगा कि ईमानदारी, मेहनत और मेरिट का कोई मतलब नहीं है, तो उनका भरोसा उठ जाएगा।

कमल हासन बोले- सिस्टम सड़ चुका

एक्टर और नेता कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के शिक्षा तंत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जब एक बच्चा रोया था, तब हमें सुन लेना चाहिए था। हमने तब तक इंतजार किया जब तक कई बच्चों की मौत नहीं हो गई। एक ऐसा सिस्टम जहां सीखने की जगह कोचिंग ने ले ली है, उत्सुकता की जगह चिंता ने ले ली है और मेरिट की जगह अपराध ने ले ली है, वह सिस्टम पूरी तरह सड़ चुका है।

खेसारी लाल यादव पर बुरी तरह भड़कीं मलाइका अरोड़ा

वजह जानकर आपको भी आ सकता है गुस्सा

नई दिल्ली, एजेंसी

बॉलीवुड की क्वीन मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के एक वीडियो पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस क्लिप पर जब मलाइका की नजर पड़ी तो वह अपनी नाराजगी जताने से पीछे नहीं रहीं। यह वीडियो एक इवेंट का है, जहां खेसारी लाल यादव आए थे। जब वह पैपराजी को पोज देने के लिए आए तो वहां एक डॉग लेटा हुआ था। जिसे उन्होंने हटवाया। जब वह डॉग नहीं हट रहा था, तब कभी शख्स ने पैर से उसे खिसकाया तो कभी उसे हाथ से घसीट कर खेसारी के पास से ले गए। यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। इस बीच मलाइका अरोड़ा भी अपना गुस्सा जताने में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने गुरुवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर खेसारी का वही वीडियो रीशेयर किया और अपनी भड़ास निकाली। मलाइका अरोड़ा का खेसारी को लेकर किया गया ये पोस्ट अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि एक्ट्रेस हमेशा से ही डॉग लवर्स रही हैं ।

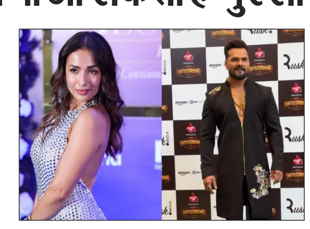

'सैयारा' के बाद ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे अहान पांडे

नई फिल्म की रिलीज डेट का एलान, 2027 में दस्तक देगी मूवी

नई दिल्ली। फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अहान पांडे (Ahaan Panday) की अगली फिल्म का इंतजार दर्शकों को बड़ी बेसब्री से है। अहान की अगली फिल्म का एलान काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई है कि आखिर अली अब्बास जफर की ये अनटाइटल्ड मूवी पर्दे पर कब दस्तक देगी।

अहान पांडे के साथ इस फिल्म में शरवरी नजर आएंगीं। फिल्म का इंतजार दर्शकों को काफी वक्त से है। इस एक्शन फिल्म को अली अब्बास जफर बना रहे हैं और अब YRF ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने अली अब्बास जफर की इस अनटाइटल्ड फिल्म के लिए 26 मार्च, 2027 की रिलीज डेट तय की है।

मतलब यह है कि फिल्म 2027 में गुड फ्राइडे के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि फिल्म में अहान-शरवरी (Sharvari) ही नहीं होंगे, बल्कि फिल्म में आपको अभिनेता बॉबी देओल (Bobby Deol) भी नजर आएंगे और फिल्म में बॉबी की दमदार एंट्री से धमाका जरूर होगा। वहीं फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे भी होंगे।

हालांकि इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों को ये जानने की उत्सुकता है कि फिल्म में आखिर एक्शन का लेवल कितना ज्यादा होगा। दरअसल फिल्म में एक्शन बड़े लेवल पर नजर आएगा। अब फिल्म को डायरेक्ट करने की कमान अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) ने संभाली है तो जाहिर फिल्म में एक्शन धमाकेदार ही होगा। अली अब्बास जफर इससे पहले गुंडे और टाइगर जैसी शानदार फिल्में बना चुके हैं। ऐसे में इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा में मसाला भरपूर होगा।

8 साल बाद जॉनी डेप का धांसू कमबैक

हॉरर थ्रिलर एबेन्सर के ट्रेलर में 'खडूस बूढ़ा' बनकर कर दिया हैरान

नई दिल्ली। हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जॉनी डेप (Johnny Depp) को 8 साल से बड़े पर्दे पर देखने का फैंस इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार अभिनेता कमबैक के लिए तैयार हैं। वह एक अलग अंदाज में वापसी कर रहे हैं और उनकी आगामी फिल्म का ट्रेलर देख लोगों के होश उड़ गए।

जॉनी डेप की कमबैक फिल्म एबेनेजरः एक क्रिसमस कैरोल (Ebenezer: A Christmas Carol) है। यह एक क्रिसमस फैंटेसी हॉरर थ्रिलर है जिसका निर्देशन टी. वेस्ट ने किया है। फिल्म में जॉनी डेप के अलावा अहम भूमिकाओं में एंड्रिया राइजबोरो, सैम क्लैफ्लिन, डेजी रिडले, आर्थर कोंटी, एली बैम्बर, चार्ली मर्फी और इयान मैककेलन जैसे कलाकार हैं।

फिल्म चार्ल्स डिकेंस की 'अ क्रिसमस कैरोल' (A Christmas Carol) पर बेस्ड है जिसमें एक कठोर और कंजूस बूढ़े आदमी एबेनेजर स्क्रूज की कहानी बताई गई है। एबेनेजर को क्रिसमस के त्योहार से नफरत है। क्रिसमस Eve से ठीक एक दिन पहले उसके मरे हुए बिजनेस पार्टनर जैकब मार्ले का भूत और तीन आत्माएं आती हैं और उसे उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिखाती हैं।

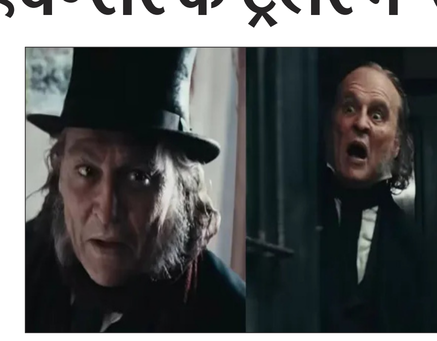

भूत और आत्माएं मिलकर उसे किस तरह बदल देती हैं, कहानी इसी के इर्द-गिर्द है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एबेनेजर (जॉनी डेप) आत्माओं से परेशान हो गया है।

जॉनी डेप की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म सिनेमाघरों में 13 नवंबर को रिलीज होने वाली है। साल 2018 के बाद से यह जॉनी का का पहला बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट है। फैंस उन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं।

रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर

जॉनी डेप की फिल्म एबेनेजरः एक क्रिसमस कैरोल हॉरर के साथ-साथ कॉमेडी से भी भरी है, जिसकी एक झलक फिल्म के ट्रेलर में साफ दिखाई दे रही है। 24 जुलाई को रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर कॉमेडी, ड्रामा और हॉरर से भरी हुई है जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। फिल्म का सबसे बड़ा हाइलाइट 63 साल के जॉनी का लुक है। आप उन्हें एक पल के लिए पहचान नहीं पाएंगे।

जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई, पहले के 15% टैरिफ का आज आखिरी दिन

अमेरिका ने भारत पर 10% टैरिफ लगाया

फैसला

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिका ने शुक्रवार से भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है। यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत फोर्स्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से बने सामान को लेकर की गई है।

यह फैसला ऐसे दिन लागू हुआ, जब ट्रम्प प्रशासन का 15% अस्थायी ग्लोबल टैरिफ खत्म हो रहा है। यानी पुराना टैरिफ हटते ही उसकी जगह नया स्थायी टैरिफ लागू कर दिया गया।

अमेरिका ने 60 देशों पर 10% से 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। इनमें 17 देशों पर 10% और 43 देशों पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका को 10% वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका के मुताबिक, इन देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर रोक लगाई है या उस दिशा में कदम उठाए हैं। शुरुआत में भारत पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। हालांकि बाद में भारत सरकार की ओर से श्रम मानकों और सप्लाई चेन की निगरानी से जुड़े कुछ नीतिगत सुधारों तथा अमेरिका के साथ लगातार बातचीत के बाद इसे घटाकर 10% कर दिया गया।

फेडरल नोट में कहा गया है कि जून में प्रस्तावित टैरिफ घोषित होने के बाद भारत ने 14 जून को अपनी विदेशी व्यापार नीति में संशोधन किया। अमेरिका का मानना था कि भारत ने श्रमिक अधिकारों की निगरानी, नियमों के पालन और सप्लाई चेन में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसी आधार पर प्रस्तावित टैरिफ में 2.5% की राहत दी गई।

10% टैरिफ लागू रहने का मतलब है कि भारत को पूरी छूट नहीं मिली है। यानी अमेरिका अब भी चाहता है कि भारत श्रम मानकों और फोर्स्ड लेबर से जुड़े नियमों को और प्रभावी ढंग से लागू करे। हालांकि 12.5% के बजाय 10% टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर पड़ने वाला अतिरिक्त लागत का बोझ कुछ कम होगा। फोर्स्ड लेबर का मतलब ऐसी मजदूरी से है, जिसमें किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के खिलाफ काम कराया जाए।

भारत के किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में अतिरिक्त 10% टैरिफ से उन सेक्टर्स पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अधिक है। इनमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर उत्पाद, कृषि एवं फूड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम शामिल हैं।

अतिरिक्त टैरिफ लगने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इससे खरीदार दूसरे देशों के विकल्प तलाश सकते हैं या भारतीय निर्यातकों पर कीमत घटाने का दबाव बढ़ सकता है।

> अमेरिका का कहना है कि अगर किसी देश से आयात होने वाला सामान फोर्स्ड लेबर से जुड़ा पाया जाता है, तो उस पर अतिरिक्त टैरिफ या आयात प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों पर दबाव बनाना है कि उनकी सप्लाई चेन में जबरन मजदूरी का इस्तेमाल न हो।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन देंगे इस्तीफा

शेख हसीना के साथ संबंधों के लगे हैं आरोप

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही शुक्रवार को इस्तीफा दे देंगे। वह सत्ता से बेदखल की गईं प्रधानमंत्री शेख हसीना के पूर्व सहयोगी रहे हैं। यह घटनाक्रम हसीना के उस बयान के कुछ दिनों बाद सामने आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद स्वदेश लौट रही हैं। शहाबुद्दीन के प्रवक्ता ने उनके इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई है। हालांकि, मामले की जानकारी रखने वाले तीन अधिकारियों ने बताया कि शेख हसीना के साथ पुराने संबंधों को देखते हुए सरकार ने उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव डाला है। शहाबुद्दीन के त्यागपत्र के बाद शीर्ष पदों पर हसीना का कोई सहयोगी नहीं बचेगा। उनकी बांग्लादेश वापसी की योजना में अभी पांच महीने बाकी हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनकी पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है या वे भूमिगत हो गए हैं। शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश सरकार के लिए एक चुनौती होगी, जो देश में स्थिरता बहाल करने का प्रयास कर रही है।

प्रेट् के अनुसार, अखबार प्रथम आलो ने सरकार के एक उच्च-स्तरीय सूत्र के हवाले से कहा है कि सरकार उन खबरों से नाराज है जिनमें कहा गया है कि शहाबुद्दीन ने हाल ही में हसीना से फिर से संपर्क साधने की कोशिश की थी।

फास्ट न्यूज

चांदी आज 2,924 सस्ती, 2.19 लाख पर आई

नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में आज यानी 24 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 2,924 रुपए घटकर 2.19 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,848 रुपए गिरकर 1.42 लाख रुपए पर आ गया है। एक दिन पहले चांदी 2.22 लाख रुपए और सोना 1.44 लाख रुपए पर था।

सेंसेक्स 331 अंक गिरकर 76,059 पर बंद

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 24 जुलाई को गिरावट रही। सेंसेक्स 331 अंक की गिरावट के साथ 76,059 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 102 अंक की गिरावट है, ये 23,767 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। ब्रेंट क्रूड आज 96 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा, तो तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल-डीजल पर दिख सकता है।

आशीष कुमार दश होंगे इंफोसिस के नए सीईओ

नई दिल्ली। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी इंफोसिस ने आशीष कुमार दश को अपना नया CEO नियुक्त किया है। 23 जुलाई 2026 को पहली तिमाही के नतीजों के साथ कंपनी ने इस लीडरशिप बदलाव का ऐलान किया। वे मौजूदा CEO और MD सलिल पारिख की जगह लेंगे।

यरुशलम में भारतीय मजदूर की हत्या फ्लैट में खून से लथपथ मिली लाश

यरुशलम, एजेंसी

इजरायल में काम करने वाले एक भारतीय व्यक्ति का शव यरूशलम के कटामोन इलाके एक अपार्टमेंट में मिला है। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि 40 वर्षीय व्यक्ति का शव घर के फर्श पर पड़ा मिला और उसके चारों ओर खून फैला हुआ था।

मोरियाह पुलिस स्टेशन के प्रमुख युवल रूबेन ने बताया कि पुलिस को पीड़ित का शव घर में पड़ा हुआ, जिसके चारों ओर काफी खून फैला था। पुलिस ने कहा कि मौत की असली वजह अभी साफ नहीं है। इजरायली अधिकारियों ने अभी तक पीड़ित की पहचान जाहिर नहीं की है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच से आपराधिक पहलू का संकेत मिलता है। पुलिस ने दक्षिणी शहर इलात के एक 31 वर्षीय व्यक्ति को हत्या में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया है। संदिग्ध को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2024 तक इजरायल में लगभग 32,000 भारतीय कामगार थे। मंत्रालय ने बताया कि इनमें से लगभग 12,000 भारतीय अक्टूबर 2023 के बाद पहुंचे। नवंबर 2023 में हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत 6,365 भारतीय 2024 में इजरायल पहुंचे, जबकि बाकी लोग निजी माध्यमों से गए।

फरवरी में भारत और इजरायल इस बात पर सहमत हुए थे कि अगले पांच वर्षों में 50,000 और भारतीय कामगार इजराइल आ सकते हैं। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बैठक में लिया गया था। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इजराइल में भारतीय कामगारों के योगदान को सराहा था।

भारत और चीन के राजदूतों से मुलाकात करेंगे

नेपाली पीएम बालेन शाह ने अपना ही नियम क्यों तोड़ा

काठमांडू, एजेंसी

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन शाह) पहली बार अपने बनाए नियम से हटकर विदेशी राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने तय किया था कि वह किसी भी विदेशी राजदूत से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे।

नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बालेन शाह भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीन के राजदूत झांग माओमिंग से अलग-अलग मुलाकात करेंगे।

इसे नेपाल की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह अपने दोनों सबसे बड़े पड़ोसियों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखना चाहता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हितों का टकराव पैदा होता था और नेपाल के राष्ट्रीय हित प्रभावित होते थे। बालेन शाह ने तय किया कि वह किसी भी विदेशी राजदूत या प्रतिनिधि से अकेले मुलाकात नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक अलग 'रैंक प्रोटोकॉल' बनाया था। नए नियम के मुताबिक, वह सिर्फ किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष/प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री स्तर के अधिकारी से ही अकेले व्यक्तिगत बैठक करेंगे। निचले स्तर के अधिकारियों, राजदूतों या उप-मंत्रियों से वे अकेले मिलने के बजाय विदेश मंत्रालय के माध्यम से या फिर ग्रुप मीटिंग के जरिए ही मिलेंगे।

बालेन शाह ने 27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।

बालेन शाह के पीएम बनने से पहले का नियम क्या था?

नेपाल में नई सरकार बनने पर खासकर भारत, चीन और अमेरिका जैसे प्रभावशाली देशों के राजदूत सीधे प्रधानमंत्री के निजी आवास पर जाकर अलग-अलग मुलाकात करते थे। इन बैठकों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद नहीं होते थे और न ही इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता था।

3 महीने में ही फैसले से पलटे

बालेन शाह ने पीएम बनने के बाद विदेशी राजनयिकों से सिर्फ समूह (ग्रुप) में मुलाकात करने की नीति अपनाई।

एक ही दिन दोनों देशों के राजदूतों के साथ मीटिंग

बालेन शाह नहीं चाहते थे कि भारत या चीन में से किसी को यह लगे कि दूसरे देश को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने दोनों देशों के राजदूतों से एक ही दिन अलग-अलग मुलाकात करने का फैसला किया है। दोनों बैठकें एक के बाद एक होंगी, ताकि दोनों देशों के साथ समान व्यवहार का मैसेज जाए। नेपाल सरकार ने पुष्टि की है कि भारत और चीन के राजदूतों के साथ अलग-अलग बैठकें इसी सप्ताह होंगी। हालांकि, दोनों बैठकों की सटीक तारीख अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। नेपाल का विदेश मंत्रालय इन बैठकों की अंतिम तैयारियों में जुटा है।

नई शर्त जोड़ी, बोले- इजराइल से रिश्ते सुधारे सऊदी, न्यूक्लियर डील अटकी

सऊदी से परमाणु समझौता करके 24 घंटे में पलटे ट्रम्प

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब दो दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी, जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा।

ट्रम्प ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं मिलेगी।

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प की घोषणा से सऊदी अरब भी हैरान रह गया। समझौते के मसौदे में कुछ शर्तें पूरी होने पर सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलने की बात थी, लेकिन ट्रम्प ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया।

दोनों देशों ने करीब दो दशक पहले परमाणु ऊर्जा सहयोग की पहल की थी। पिछले साल अक्टूबर में प्रारंभिक सहमति बनी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध और कांग्रेस की संभावित आपत्तियों के कारण समझौता महीनों तक अटका रहा। पिछले सप्ताह ऊर्जा विभाग को लगा कि ट्रम्प की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसकी घोषणा कर दी गई।

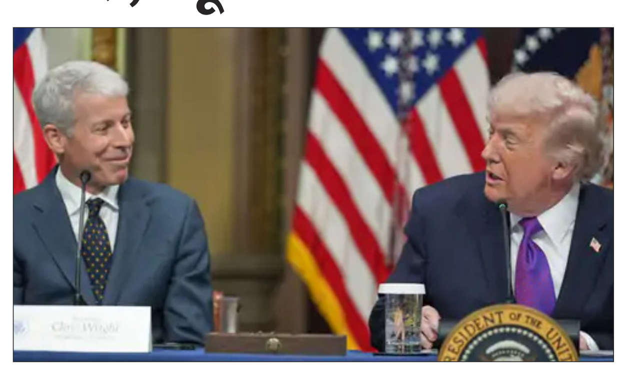

बिना बताए डील की घोषणा से ट्रम्प नाराज

वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प इस बात से नाराज थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर दी। इसके बाद फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस ने ऊर्जा विभाग से समझौते की घोषणा टालने को कहा था, लेकिन विभाग ने हस्ताक्षर समारोह भी किया और मीडिया में इसकी जानकारी भी दी। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स की शर्त शुरू से ही ट्रम्प की नीति का हिस्सा थी। वहीं ऊर्जा विभाग ने किसी भी मतभेद से इनकार किया।

क्वांटस के प्रोजेक्ट सनराइज की पहली टेस्ट फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया पहुंची

फ्रांस से 19 घंटे की उड़ान भरकर इतिहास बनाया

नई दिल्ली, एजेंसी

ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन क्वांटस के विमान ने सबसे लंबी दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार 24 जुलाई की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लैंडिंग की।

विमान ने फ्रांस के टूलूज शहर से स्थानीय समयानुसार गुरुवार सुबह 7:33 बजे उड़ान भरी थी। 19 घंटे और 13 मिनट का लंबा सफर तय करके इसने मेलबर्न में टचडाउन किया। इस ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट के दौरान एयरबस के 4 पायलट और 5 फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर विमान में मौजूद थे। टेस्ट फ्लाइट का मुख्य मकसद जेट के स्पेशल फ्यूल सिस्टम को जांचना था।

इस विमान में 20 हजार लीटर का एक अतिरिक्त रियर सेंटर फ्यूल टैंक है, जो आम A350-1000 एयरक्राफ्ट्स में नहीं होता है। यह फ्यूल टैंक विमान को 22 घंटे तक लगातार उड़ने की क्षमता देता है।

क्वांटस के मुताबिक, यह विमान मेलबर्न से वापस टूलूज स्थित एयरबस मुख्यालय लौटेगा। इस वापसी यात्रा में क्वांटस के 2 पायलट और एयरबस का टेस्ट क्रू सवार रहेगा। क्वांटस ने साल 2017 में पहली बार 'प्रोजेक्ट सनराइज' का ऐलान किया था और 2022 में एयरबस को 12 कस्टमाइज्ड A350-1000ULR एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। पहले विमान की डिलीवरी इसी साल होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी हुई है और पहला विमान अप्रैल 2027 में मिलेगा। इसके बाद बाकी 11 विमान अगले ढाई सालों में डिलीवर किए जाएंगे।

आरोप : बिना अनुमति एआई ट्रेनिंग में किताबों का किया था इस्तेमाल

एंथ्रोपिक हैरी पॉटर के पब्लिशर को देगी 19 मिलियन डॉलर का मुआवजा

वाशिंगटन, एजेंसी

AI कंपनी ने अपने चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए बिना इजाजत हैरी पॉटर और कई अन्य किताबों का डेटा इस्तेमाल कर लिया था। अब 'हैरी पॉटर' किताबें छापने वाली कंपनी 'ब्लूम्सबरी' को AI बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक से करीब 19 मिलियन डॉलर मिलने की संभावना है। दरअसल, एंथ्रोपिक पर आरोप था कि उसने अपने 'क्लाउड' (Claude) AI मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बिना अनुमति और खरीदारी के हजारों कॉपीराइट वाली किताबों का इस्तेमाल किया।

यह मुकदमा उन लेखकों द्वारा दायर किया गया था जिन्होंने आरोप लगाया था कि एंथ्रोपिक ने अपने क्लाउड एआई चैटबॉट को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी पुस्तकों का बिना अनुमति के उपयोग किया था। अमेरिकी इतिहास में कॉपीराइट का यह अब तक का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है। हालांकि, इस समझौते के तहत एंथ्रोपिक को अपनी गलती स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उन एआई कंपनियों के लिए अब तक के सबसे स्पष्ट वित्तीय परिणामों में से एक है जिन पर बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने का आरोप है।

> मुकदमा दायर होने के बाद एक अमेरिकी कोर्ट ने समझौते के दायरे में आने वाली अपनी 14,087 पुस्तकों की पहचान की, जिसमें प्रति पुस्तक लगभग 3,000 डॉलर के मुआवजे का प्रस्ताव है, मुआवजे की इस राशि को संबंधित लेखकों और प्रकाशकों के बीच बांटा जाएगा।

नकल करके बनाए गए एआई मॉडल

प्रकाशकों, लेखकों, समाचार संगठनों और कलाकारों की बढ़ती संख्या ने एआई कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। उनका आरोप है कि उनकी रचनाओं की नकल करके बिना सहमति या मुआवजे के शक्तिशाली एआई मॉडल बनाए गए हैं।

दूसरों की किस्मत बताने वाली खुद नहीं जान पाई अपना भविष्य!

मॉस्को में पावर बैंक फटने से झुलसीं इन्फ्लुएंसर अन्ना

मॉस्को, एजेंसी

रूस की महिला इन्फ्लुएंसर और ज्योतिष अन्ना ओटाविना के मॉस्को स्थित पेंटहाउस में रात के समय बिस्तर पर रखा पावर बैंक फट गया। पावर बैंक ओवरहीट होकर ब्लास्ट हुआ, इससे अन्ना ओटाविना की पीठ का 30 फीसदी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया और बाल भी जल गए।

इस घटना के बाद अन्ना ने अपने फॉलोअर्स को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है कि सोते समय या बिस्तर जैसी नरम सतहों पर पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्जिंग पर छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है।

वहीं इस घटना के बात इस बात की भी चर्चा हो रही है कि दूसरों की किस्मत बताने वाली ज्योतिष खुद का भविष्य नहीं जान पाईं, जिसके कारण इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा।

अन्ना ओटाविना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि उनका पोर्टेबल चार्जर, जिसे उन्होंने फोन चार्ज करने के लिए बिस्तर पर रखा था, अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। जिसके कारण ब्लास्ट हो गया और वो घायल हो गईं।

ओटाविना का कहना है पावर बैंक इसलिए ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वह इसे किसी ठोस, हवादार सतह के बजाय नरम बिस्तर पर रख दी थी, जिसके कारण वह बहुत गर्म हो गया। वह पावर बैंक की ओर पीठ करके सो रही थी, जिसके कारण पीठ का लगभग 30 फीसदी हिस्सा जल गया और बाल भी झुलस गए।

जैसे ही वह उछली, आग की लपटें उनके बालों तक पहुंच चुकी थीं। जलते हुए, बाल उसकी पीठ पर गिरे और उसकी त्वचा को झुलसा दिया, इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि क्या हो रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि स्थिति एक छोटी सी चिंगारी से कहीं अधिक गंभीर थी। उनके तकिया और कंबल जल रहे थे, और पावर बैंक जमीन पर गिर गया था।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है। मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676